राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रसारीत

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार, 10 जून-2021 वर्ष-4, अंक -137 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
YouTube Linked in
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023 (Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

कोरोना के कारण गई 400 कर्मियों की जान, कोल इंडिया ने लगाई गुहार, 10 लाख टीके दे सरकार

नई दिल्ली। अपने 400 कर्मचारियों को कोरोना के कारण खोने के बाद अब कोल इंडिया लिमिटेड ने मोदी सरकार से अपने कर्मचारियों के लिए टीके की मांग की है। कोल इंडिया में करीब 2 लाख 59 हजार कर्मचारी काम करते हैं। अब कंपनी ने कहा है कि उसने सरकार को चिट्ठी लिखकर अपने स्टाफ और उनके परिवार वालों के लिए कोरोना रोधी टीके की 10 लाख खुराकें मांगी हैं। कंपनी के मुताबिक, अभी तक उसके 64 हजार कर्मचारियों ने टीका लिया है लेकिन अब वह अपने सभी कर्मियों को तेजी से टीका लगाना चाहती है। मजदूरों के जाने-माने संगठनों में से एक अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के जनरल सेक्रटरी सुधीर घुर्दे कहते हैं, कंपनी बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू कर के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को टीका देना चाहती है ताकि वायरस को नियंत्रित किया जा सके। कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मी इस महामारी में लॉकडाउन के दौरान भी लगातार काम कर रहे हैं ताकि पावर प्लांटों चलते रहें। इस साल फरवरी में शुरू हुए कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हजारों-लाखों मौतों के बावजूद कोयला खदानों में काम चलता रहा है। कोल इंडिया ने कहा है कि अधिकतर मौतें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई हैं। हालांकि, अब स्थिति सुधरने लगी है लेकिन इसकी तीसरी लहर आने की आशंका के बीच कंपनी ने अब कुछ समय के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी कर रही है और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी तैयारी कर रही है। अभी तक कंपनी के कुल 6 हजार कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1000 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर हालांकि अब मंद पड़ रही है लेकिन इस संक्रमण ने देश के 3 लाख 51 हजार से ज्यादा नागरिकों की जान ले ली है।

पहली बारिश में ही थम गई मुंबई की रफ्तार, कई जगह भारी ट्रैफिक जाम, हाई टाइड की चेतावनी

मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई का बेहाल हो गया। सड़कों के जलमग्न होने से भारी ट्रैफिक लग गया। वहीं पटरियों पर पानी भरने के चलते कई ट्रेनें लेट चल रही हैं तो कई के पहिए थम गए। भारत विज्ञान मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक आने वाले 48 घंटे तक मुंबई में इसी तरह से तेज बारिश होती रहेगी। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है।

मुंबई। मानसून ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार को अपनी दस्तक दी है। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई का बेहाल हो गया। सड़कों के जलमग्न होने से भारी ट्रैफिक लग गया। वहीं पटरियों पर पानी भरने के चलते कई ट्रेनें लेट चल रही हैं तो कई के पहिए थम गए। भारत विज्ञान मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक आने वाले 48 घंटे तक मुंबई में इसी तरह से तेज बारिश होती रहेगी। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, मुंबई में 11.43 बजे हाई टाइड के आने की संभावना है। इस दौरान समुंद्र की लहरें 4.16 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में एहतियातन समुंद्र के किनारे के इलाकों

को खाली करवा लिया गया है। साथ ही कई टीमें नजर बनाए हुए हैं। आईएमडी मुंबई के उप महानिदेशक डॉ जयंत सरकार ने बताया कि महाराष्ट्र में इस बार समय से एक दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। मुंबई में मानसून के पहुंचने की तारीख 10 जून थी। इससे पहले मंगलवार को प्री मानसून की बारिश ने मुंबई को पानी-पानी कर दिया। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसके कारण यातायात भी कई जगह बाधित रहा। मुंबई के हिंदमाता में सड़कों पर जल जमाव दिखा।

रेलवे ने जारी किया अलर्ट

मुंबई में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। मध्य रेलवे के सायन स्टेशन के ट्रैक पर भरी पानी जमा हो गया है। आगे में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेलवे ने सभी रिलीफ ट्रेनों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। बता दें कि भारी बारिश होने पर ट्रैक पर पानी भरने की स्थिति में उससे निपटने और लोकल सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेलवे की ओर से अलर्ट जारी किया है।

एमएमआरडीए ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

बारिश और उससे होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) ने 24 घंटे का आपातकालीन मानसून नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति परेशानी में मोबाइल नंबर 8657402090 और लैंडलाइन नंबर 02226594176 पर कॉल करके मदद की अपील कर सकता है।

अगस्त से टीके ही टीके, डीएनए वैक्सीन को लेकर भी प्रक्रिया आगे बढ़ी

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने 44 करोड़ खुराक के लिए ऑर्डर जारी किए हैं। इनमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवाक्सिन की खुराक हैं जिनकी आपूर्ति आगामी अगस्त माह से शुरू होगी। इसके लिए सरकार ने 30 फीसदी भुगतान पहले करने की सहमति जताई है। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में बायोलॉजिकल ई कंपनी को भी 1500 करोड़ रुपये का भुगतान करते हुए 30 करोड़ खुराक का ऑर्डर जारी किया था। नीति आयोग के सदस्य और टीकाकरण को लेकर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉ. वीके पॉल ने बताया कि जनवरी से जुलाई तक के लिए सरकार ने 53.60 करोड़ खुराक का ऑर्डर किया था जिनमें से करीब 25 करोड़ से अधिक खुराक अब तक प्राप्त हो चुकी हैं। बाकी खुराक भी उत्पादन के साथ आगामी दिनों में मिलती रहेंगी। हालांकि टीकाकरण को बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब दो महीने पहले ही कंपनियों को एडवांस ऑर्डर दे दिया है। इसके तहत 74 करोड़ खुराक अगस्त माह से मिलना शुरू हो जाएंगीं। इस दौरान जैसे जैसे नई कंपनियां या फिर वैक्सीन सामने आएंगी उनके लिए भी इसी प्रकार ऑर्डर जारी किए जाएंगे। डॉ. पॉल ने कहा कि अगस्त और सिंतबर के बीच देश में वैक्सीन की काफी खुराक उपलब्ध हो सकती हैं। हालांकि इससे पहले तक डॉ. पॉल और अन्य अधिकारी जुलाई माह से देश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलने की जानकारी दे रहे थे। डॉ. पॉल का कहना है कि वैक्सीन उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है। जैसे किसी महीने कंपनी छह तो अगले महीने सात या आठ करोड़ वैक्सीन दे रही है ठीक वैसे ही उसे आपूर्ति में लाया जा रहा है। ऐसे में यह कहना है कि एक निश्चित तिथि तक इतनी तय खुराक मिल पाएंगी। यह थोड़ा मुश्किल होगा।

डीएनए वैक्सीन का रास्ता साफ, जल्द आएगी सूचना

डॉ. वीके पॉल ने कहा कि डीएनए वैक्सीन को लेकर भी काफी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। उम्मीद है कि अगले कुछ सप्ताह में कंपनी की ओर से आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगी जा सकती है।

कोरोना की दूसरी लहर के बीच 16 जून को होगी लोक लेखा समिति की बैठक

कोरोना की दूसरी लहर के बीच 16 जून को होगी लोक लेखा समिति की बैठक

नई दिल्ली। अगले सप्ताह लोक लेखा समिति यानी पीएसी की बैठक बुलाई गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच यह पहली स्थायी समिति की बैठक होगी। 16 जून को होने जा रही इस बैठक में टीकाकरण नीति की समीक्षा किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सांसदों से उनके निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कोविड राहत कार्यों का ब्योरा साझा करने का आग्रह किया। सांसदों को भेजे गए पत्र में बिरला ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप इस प्रतिकूल परिस्थिति में

अपना ज्यादा समय लोगों की मदद में बिता रहे होंगे। आपने लोगों को न सिर्फ नैतिक समर्थन दिया होगा, बल्कि उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, यह वक्त की मांग है कि आप अपने स्तर पर चलाए गए राहत कार्यों और अनुभवों को पूरे देश के साथ साझा करें, ताकि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श व्यवहार का विकास किया जा सके। राजस्थान के कोटा से सांसद बिरला ने घोषणा की है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करने वाले उन छात्रों को मुफ्त में कोचिंग और आवासीय सुविधा दी जाएगी, जिन्होंने इस महामारी में माता-पिता या परिवार के कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है।

पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडेय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त

नई दिल्ली। यूपी काडर के आईएएस अफसर (सेवानिवृत) अनूप चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अनूप चंद्र 1984 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं. साथ ही उन्हें 37 साल की भारतीय प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडेय को मंगलवार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने कहा कि राष्ट्रपति ने 1984 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी पांडेय को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के रूप में सुनील अरोड़ा का

कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हो गया था। इसके बाद से निर्वाचन आयुक्त का एक पद रिक्त था। सुशील चंद्रा सीईसी हैं, जबकि राजीव कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। साल 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनने वाले अनूप चंद्र 2019 अगस्त महीने तक पद पर रहे थे। वहीं इन दिनों एनजीटी में यूपीनिगरानी समिति के मौजूदा सदस्य हैं। बता दें कि इससे पहले अनूप उत्तर प्रदेश सरकार में कई बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अनूप चंद्र पांडेय 37 साल तक उत्तर प्रदेश में अलग-अलग पदों पर रहे हैं। साल 2019, 29 अगस्त को वो यूपी के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए थे। वहीं, अनूप पांडे कई मंडलों के कमिश्नर रह चुके हैं तो वहीं कई जिलों के डीएम भी रहे हैं।

जिन्हें लगा 'नकली' टीका, उन्हें प्रमाण पत्र सहित मिलेगी प्राथमिकता

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन के परीक्षण में जिन लोगों को नकली वैक्सीन यानी प्लेसबो दिया गया था अब उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इनकी दो खुराक पूरी होने पर इन्हें प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए फॉर्मा कंपनी और जिस अस्पताल में परीक्षण हुआ, वहां का प्रबंधन जिम्मेदार होगा। जानकारी के अनुसार भारत में अभी तक वैक्सीन परीक्षण को लेकर करीब एक लाख से अधिक लोग हिस्सा ले चुके हैं। इन लोगों ने पिछले वर्ष भारत बायोटेक की कोवाक्सिन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण में हिस्सा लिया था। इस दौरान एक समूह को वैक्सीन की असली खुराक दी गई थी तो दूसरे समूह को प्लेसबो दिया था जो एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है लेकिन वैक्सीन नहीं होती है। यह पूरी प्रक्रिया बैच नंबर के आधार पर चलती है जिसके बारे में कंपनी के अलावा अन्य किसी के पास जानकारी नहीं होती है। यहां तक कि वैक्सीन लगाने वाले को भी नहीं पता होता कि यह असली है या फिर प्लेसबो। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ समिति (एसईसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परीक्षण में शामिल लोगों को अलग से वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी फॉर्मा कंपनियों की है। इसलिए जो लोग परीक्षण में शामिल हुए थे और उन्हें नहीं पता कि वैक्सीन लगा था या नहीं। ऐसे लोग उक्त केंद्र या अस्पताल में जाकर जानकारी ले सकते हैं और आगे की प्रक्रिया के बारे में भी पूछताछ कर सकते हैं। अभी तक देश में भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला, बायोलॉजिकल ई, जेनोवा, स्पूतनिक वी सहित कई वैक्सीन के परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। भारत बायोटेक के तीनों चरणों में करीब 35 हजार लोगों को परीक्षण में शामिल किया था। जबकि कोविशील्ड और स्पूतनिक वी के लिए दूसरा और तीसरा चरण का परीक्षण ही हुआ था जिनमें करीब 20 हजार लोग शामिल हुए थे।

दिल्ली एम्स ने शुरू किया टीकाकरण

- दिल्ली एम्स के अनुसार पिछले साल से अब तक उनके यहां भारत बायोटेक के कोवाक्सिन के परीक्षण किए जा चुके हैं। इनके लिए करीब दो हजार लोगों को शामिल किया गया। जिन लोगों को उस दौरान प्लेसबो मिला था उन्हें फोन करके अस्पताल बुलाया जा रहा है और वैक्सीन दी जा रही है। वहीं जिन लोगों को परीक्षण के दौरान असली वैक्सीन दी गई है उन लोगों से फोन पर आधार कार्ड मांगा जा रहा है जिसके आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा। एम्स के अनुसार प्रमाण पत्र फॉर्मा कंपनियों के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी पूरी जानकारी कोविन प्लेटफॉर्म पर भी होगी। इस जानकारी के बाद कोविन वेबसाइट पर भी उन लोगों की सूचना दर्ज कर ली जाएगी।

कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने के लिए विज्ञापन देना गलत, अवैध प्रक्रिया पर लगे रोकः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे उन एनजीओ पर कार्रवाई करें जो अवैध रूप से बच्चों को गोद ले रहे हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने आदेश में कहा कि जेजे एक्ट, 2015 के प्रावधानों के अलावा किसी और तरीके से बच्चों को गोद लेने से रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को गोद लेने के लिए आमंत्रण देना अवैध है और उन्हें कारा-सेंट्रल अडॉप्शन कंट्रोल अथॉरिटी, को शामिल कर गोद लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस गैरकानूनी काम में शामिल एनजीओ, एजेंसियों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं।

कोर्ट ने कहा कि इन एजेंसियों को बेसहारा हुए बच्चों के नाम पर फंड एकत्र करने और बच्चों को गोद लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करने से रोका जाए। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब एनसीपीसीआर द्वारा कोर्ट को बताया गया कि एनजीओ और कई लोग मीडिया में विज्ञापन देकर बच्चों को गोद लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

अब तक 30,071 बच्चे बेसहारा हुए

कोविड के कारण देश भर में अब तक 30,071 बच्चे बेसहारा हुए हैं। इनमें से 15620 बालक और 14447 बच्चियां हैं जिनकी उम्र एक माह से लेकर 18 वर्ष तक है। इन बच्चों के या तो दोनों माता पिता कोविड से मर गए हैं या माता-पिता में से एक की मृत्यु हुई है। इनमें 274 बच्चे सड़कों पर छूटे हुए मिले हैं। एनसीपीसीआर ने कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर कहा है कि 6 जून तक कोविड से अनाथ होने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 7084 और उसके बाद उत्तर प्रदेश 3172 में है। वहीं उत्तराखंड में 511, दिल्ली में 17, बिहार में 1634 और झारखंड में 217 बच्चे बेसहारा हुए हैं।

किसी बच्चे की शिक्षा प्रभावित न हो

कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को आदेश दिया कि वे ध्यान रखें कि कोविड से अनाथ या बेसहारा हुए बच्चों की शिक्षा का कार्य प्रभावित न हो। कोर्ट ने कहा कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा वहां जारी रखी जाए। जो नजी स्कूलों में थे, उन्हें सरकार देखे कि कम से कम छह माह तक उन्हीं स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने दी जाए और इस बीच उनके लिए कोई रास्ता खोला जाए।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

चीन पर गहराती शंका

अमेरिका की एक सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का वायरस चीन के वुहान की प्रयोगशाला से निकला हो सकता है। एक गोपनीय दस्तावेज में कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवमोर प्रयोगशाला ने यह बात दर्ज की है कि इस वायरस की जेनेटिक संरचना के अध्ययन से पता चलता है कि इस आशंका में दम हो सकता है। चूंकि यह प्रयोगशाला बहुत प्रतिष्ठित है, इसलिए इसकी रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। इस प्रयोगशाला ने पिछले साल ट्रंप सरकार के आखिरी दिनों में यह रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट की बात सार्वजनिक होने से पहले ही पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इस मामले की जांच करने की घोषणा कर चुके हैं। यह मुद्दा कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से ही चर्चा में रहा है। इसकी वजह यह है कि कोरोना की शुरुआत वुहान प्रांत से हुई। ऐसे में, एक आशंका यह थी कि वुहान के पशु बाजार में किसी तरह से कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसान में आ गया। दूसरी, यानी प्रयोगशाला से इस वायरस के निकलने की आशंका इसलिए हुई कि वुहान में कोरोना वायरस पर प्रयोग करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। दुनिया में ऐसी सिर्फ तीन प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से बाकी दो अमेरिका में हैं। इस दूसरी आशंका के पक्ष में सुबूत जुटाना मुश्किल था और इसका इस्तेमाल सनसनीखेज आरोप लगाने के लिए होने लगा, इसलिए लोगों का इस पर विश्वास नहीं हुआ। अमेरिका में तब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अंदाज से चीन पर आरोप लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया और दक्षिणपंथी ताकतों ने इसे एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाने का बहाना बना लिया, इससे भी इस दावे की विश्वसनीयता कम हुई। लेकिन कई प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक जांच करते रहे और उनका यह कहना है कि इस बात की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि यह शत-प्रतिशत प्रमाणित तथ्य है। हो सकता है कि कोविड-19 का वायरस प्राकृतिक तरीके से पैदा हुआ हो, लेकिन दूसरी आशंका के पक्ष में भी काफी सुराग हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि चीन का तंत्र बिल्कुल पारदर्शी और खुला नहीं है, इसलिए कोई भी जांच करना मुश्किल है। डब्ल्यूएचओ की जो टीम वहां जांच करने गई थी, उसे भी इस तरह से जांच का मौका नहीं मिला कि उससे किसी स्पष्ट नतीजे पर पहुंचा जा सके। चीन के इस रवैये से शक और ज्यादा गहरा जाता है, क्योंकि अगर प्राकृतिक कारणों से वायरस फैला, तो फिर इसमें छिपाने की कोई वजह नहीं है। इसी खबर के साथ चीन से जुड़ी एक खबर यह भी आई है कि इस साल के शुरुआती पांच महीनों में चीन के साथ भारत के व्यापार में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। भारत-चीन सीमा विवाद के चलते तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच इस साल 48 अरब डॉलर, यानी करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ। चीन इसे कुछ इस तरह प्रचारित कर रहा है कि सीमा विवाद का व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह स्थिति भारत में चिकित्सा साधनों खासकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात से पैदा हुई है, यानी इलाज भी चीन ही दे रहा है। जाहिर है, भारत को चीन के बरक्स अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत सारे बुनियादी काम करने होंगे।

जनहित याचिकाओं पर न्यायालय का कड़ा रुख

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

फिल्म अभिनेत्री जूही चावला पर कोर्ट द्वारा बीस लाख रुपए का जुर्माना लगाना हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीवाय चन्द्रचूड़ द्वारा पहले से निपटाए जा चुके केस की दुबारा सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी, अपने आप में गंभीर है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. खेहर ने सस्ती लोकप्रियता के नाम पर न्यायालयों के दुरुपयोग पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संदेश दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 5 जी मामले में जूही चावला द्वारा दायर याचिका पर गहरी आपत्ति व्यक्त करते हुए इसे सस्ती लोकप्रियता करार दिया। इसमें दो राय नहीं कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण होने के साथ ही न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करने में सहायक होगी। जस्टिस खेहर ने एक जनहित याचिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अमृतधारा नहीं जिसका हर बीमारी के इलाज में उपयोग किया जा सके। दरअसल पिछले कुछ समय से छोटी से छोटी समस्या को भी जनहित याचिका के रुप में न्यायालयों में दाखिल कर उस पर न्या य मांगा जाने लगा है। याचिकाकर्ता को जहां इससे सुर्खियां बटोरने का मौका मिल जाता है वहीं कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के काम में अनावश्यक रुप से न्यायालयों का दखल देखे जाना लगता है। इसके साथ ही इस तरह की याचिकाओं के चलते न्यायालयों पर काम का बोझ भी बढ़ता है। सर्वोच्च न्यायालय कई बार इस तरह की बेबुनियाद सस्ती लोकप्रियता या छिपे हुए एजेंडे को लेकर दायर याचिकाओं पर कड़ी टिप्पणी की जा चुकी है। उदाहरण के लिए भारत का नाम बदल कर हिन्दुस्तान करने, अरब सागर का नाम सिन्धु सागर करने, राष्ट्र्गान या इसी तरह के अन्य विषयों को लेकर जनहित याचिकाएं लगाकर सुर्खियां बटोरने वालों की कमी नहीं है। दरअसल 80 के दशक में पवित्र उद्देश्य से न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने साधनहीन गरीब न्याय से वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए पोस्टकार्ड को ही याचिका के तौर पर स्वीकार कर नई शुरुआत की। राजस्थान में भी तत्कालीन न्यायमूर्ति गुमान मल लोढ़ा ने सुधार की इस कड़ी में बड़ा नाम कमाया पर समय के साथ कुछ लोगों ने इसे हथियार के रुप में उपयोग करना आरंभ कर दिया। त्वरित न्याय और न्यायालयों में न्याय के बोझ को कम करने की उद्देश्य से शुरू की गई इस व्यवस्था का लोगों ने नाम कमाने और कुछ लोगों द्वारा तो अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। जूही चावला का हालिया केस भी इसका एक उदाहरण है। यह सही है कि जनहित याचिकाओं के लगाने का प्रावधान समाज के व्यापक हित में किया गया था पर आज इसका उपयोग एक सीमा से अधिक होने लगा है। मध्य प्रदेश, उडीसा और उत्तरप्रदेश की एंबुलेंस नहीं मिलने की घटना को लेकर जनहित याचिका के रुप में सर्वोच्च् न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर जस्टिस खेहर को टिप्पणी करने को मजबूर होना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा इस तरह की याचिकाओं को लेकर जो सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं उसकी सराहना की जानी चाहिए। इसकी तारीफ इस मायने में की जानी चाहिए कि प्रशासन को भी तो काम करने दिया जाना चाहिए। इस तरह की याचिकाओं के चलते जहां एक और न्यायालयों का दैनिक काम बाधित होता है, काम का बोझ बढ़ता है, वहीं सरकार के संबंधित विभाग भी कुछ करने की जगह इन याचिकाओं के लिए जवाब दावे पेश करने में अपना समय जाया करने लगते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अमला भी न्यायालय के निर्देशों की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धर बैठ जाता है। इसका प्रतिकूल परिणाम ही प्राप्त होता है और जिस तरह से व्यवस्था में सुधार होना चाहिए वह धरा ही रह जाता है। इस तरह की पहल राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी होनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय की जूही चावला के केस में टिप्पणी और सजा इस दिशा में बढ़ता कदम माना जाना चाहिए। दरअसल इस तरह के मुद्दों को मीडिया खासतौर से इलेक्ट्रोनिक मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा तवज्जो देते हुए प्रसारित करता हैं वहीं सोशियल मीडिया पर भी क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चल पड़ता है। अब इसे यों भी देखा जा सकता है कि जूही चावला के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और जिस तरह से 5 जी मामलें में न्यायालय द्वारा 20 लाख का जुर्माना और कड़ी टिप्पणी की गई है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जूही चावला ने सभी टीवी चैनलों और अखबारों में सुर्खियां तो बटोर ही ली। हमें न्यायालय के हालिया टिप्पणी और सजा को इस मायने में भी देखना होगा कि आज देश के न्यायालयों में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। एक मोटे अनुमान के अनुसार कोरोना से पहले देश के उच्च न्यायालयों में 49 लाख से अधिक मुकदमें दर्ज है। इसी तरह से नीचे की अदालतों में करीब पोने 3 करोड़ मुकदमें विचाराधीन है। वर्ष 2014 में विधि आयोग के प्रतिवेदन में 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी। यह तो दूर की बात है पर इस समय तो देश के उच्च न्यायालयों में आधे से कुछ ही कम पद न्यायाधीशों के खाली है। इसे अलावा नीचली अदालतों में भी रिक्त पद चल रहे है। देश के न्याय के मंदिरों में काम का बोझ अत्यधिक है और यही कारण है इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भावुकता मानने के स्थान पर स्थिति की गंभीरता और उनके दर्द को समझना होगा। अब तो देश के सभी राज्यों में लोक अदालतों का सिलसिला भी चल निकला है। प्रतिवर्ष इन लोक अदालतों में लाखों प्रकरण आपसी समझाइश से निपटाए जा रहे हैं। फिर हमें देखना यह भी है कि समूची दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। सभी स्थानों पर काम प्रभावित हो रहे हैं, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। न्यायालयों द्वारा भी वर्चुअल सुनवाई की जाने लगी है उस दौर में इस तरह की याचिकाओं के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। न्यायालयों में बढ़ते बोझ को कम करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को साझा प्रयास करने होंगे। सरकार और प्रशासन को भी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। जब जनहित से जुड़े मुद्दों पर मीडिया ट्रायल हो जाता है तो ऐसे में प्रशासन को भी आगे बढ़कर मीडिया या अन्य माध्यमों से सामने आने वाले जनहित के मुद्दों का हल प्राथमिकता से निकालना चाहिए। आखिर सरकार है किसके लिए, सरकार जब आमजन के लिए ही है तो फिर ऐसे प्रकरणों के सामने आते ही संबंधित प्रशासनिक कारिंदों को सक्रिय हो जाना चाहिए। इससे एक और जहां सरकार की संवेदनशीलता सामने आती है वहीं भविष्य के लिए सुधार भी हो जाता है। अनावश्यक या कम महत्व के मुद्दों को लेकर सरकार और न्यायालयों का समय जाया नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को यह समझना होगा कि यदि सबकुछ न्यायालय के निर्देशों पर ही होने लगेगा तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी ही नहीं। न्यायपतियों की टिप्पणी की इस मायने में सराहना की जानी चाहिए कि वे न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और व्यर्थ की याचिकाओं को हतोत्साहित कर देश को सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। वकीलों के संगठनों को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

'आज के ट्वीट

योजना

'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह एक हजार रूपए और अधिकतम 12 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष एक हजार 450 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा।

-- मु.अशोक गहलोत

ज्ञान गंगा

युवा और नशा

आचार्य रजनीश ओशो/ नशीले पदार्थ सरकारों और धर्मो से अधिक शक्तिशाली प्रमाणित हुए हैं, क्योंकि किसी ने नशीले पदार्थ लेने वालों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास नहीं किया सारे धर्म और सरकारें सदा से नशीलें पदार्थों के विरुद्ध रही है: सभी धर्मो की हमेशा से यही कोशिश रही है कि लोग नशीली दवाएं न लें। सरकारों ने भी हमेशा नशीले पदाथरे का विरोध किया है, लेकिन धर्म और सरकारें इसलिए नशीले पदार्थों के विरुद्ध रही है क्योंकि वे मनुष्य को दुखी और पीड़ित ही देखना चाहते हैं। पीड़ा में मनुष्य कभी विद्रोही नहीं हो सकता। जब वह बहुत दुखी और भीतर से टूट रहा होता है तो वह एक नये समाज, एक नई संस्कृति, एक नये मानव और एक नये युग की कल्पना भी नहीं कर सकता। अपने दुख के कारण वह सहजता से पंडितों और पुजारियों का शिकार बन जाता है। वे उसे सांत्वना देते हैं, उससे कहते हैं कि धन्य हैं वे जो गरीब हैं, धन्य हैं वे जो विनम्र हैं, धन्य हैं वे जो दुखी हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। यह पीड़ित मनुष्यता राजनीतिज्ञों के हाथों में खेलती है, क्योंकि दुखी मनुष्य को एक आशा चाहिए भविष्य में-एक बेहतर समाज की आशा, एक ऐसे समाज की आशा जहां दुख और पीड़ा न हो। वे अपनी पीड़ा को सहन कर सकते हैं अगर उन्हें दूर क्षितिज में एक स्वर्णयुग की आशा बनी रहे। और स्वर्णयुग आता ही नहीं कभी। बिल्कुल ऐसे जैसे कि मृगमरीचिका होती है-उसके पीछे तुम दौड़ते रहो, दौड़ते रहो लेकिन कभी उसे पा न सकागे। जब तक कि तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे वह और आगे खिसक जाएगी। लेकिन एक आशा बंधी रहती है। राजनीतिज्ञ वादे पर जीता है। पंडित वादे पर जीता है, परंतु पिछले दस हजार वर्षो में किसी ने कुछ किया? नहीं किया। उनके नशीले पदाथरे के खिलाफ होने का कारण यह है कि नशीले पदार्थ उनका व्यवसाय बंद कर देंगे। अगर लोगों ने अफीम, एल.एस. सी., गांजा, चरस लेना शुरू कर दिया तो उन्हें न तो राजनीति की चिंता होगी, न कल क्या होगा इसकी चिंता, न इसकी चिंता कि मरने के बाद क्या होगा, न ईश्वर की और न ही स्वर्ग और नर्क की। वे उस क्षण में तृप्त हो जाएंगे। इसलिए धर्मो और संस्कारों का यह सारा विरोध है। अब तुम यह गहरी साजिश देखते हो-उनका कोई लेना-देना उस व्यक्ति के भले से नहीं है जो नशीली दवाएं ले रहा है, उनको सामाजिक ढर्रे को बरकरार रखकर अपना व्यवसाय जारी रखना है।

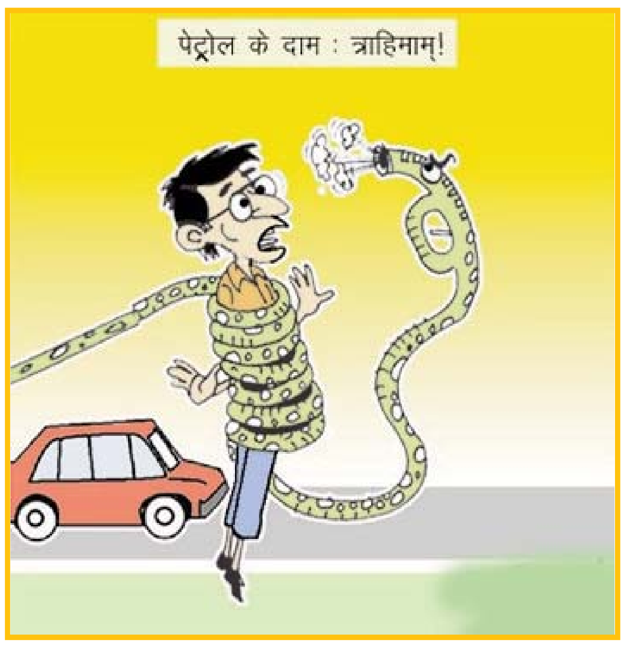

आज का राशिफल

मेष व्यावसायिक व पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जारी प्रयास सार्थक होंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शासन सत्ता से तनाव मिलेगा। गृह सुख में कमी रहेगी।

वृषभ बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक योजनायें सफल होंगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

मिथुन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। उदर विकार या नेत्र विकार की संभावना है। पारिवारिक जनों से पीड़ा मिलने के योग हैं। वाणी की सौम्यता व्यर्थ के विवादों से आपको बचा सकती है।

कर्क पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खान-पान में संयम रखें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

सिंह पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। धन लाभ की संभावना है।

कन्या पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। मांगलिक कार्यो में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

तुला जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

वृश्चिक परिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

धनु पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा।

मकर आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। वाद विवाद की स्थिति आपके हित में न होगी।

कुम्भ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। भारी व्यय का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

मीन व्यावसायिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। वाणी की असभ्यता आपको किसी संकट में डाल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शासन सत्ता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

असहमति लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा

अनूप भटनागर

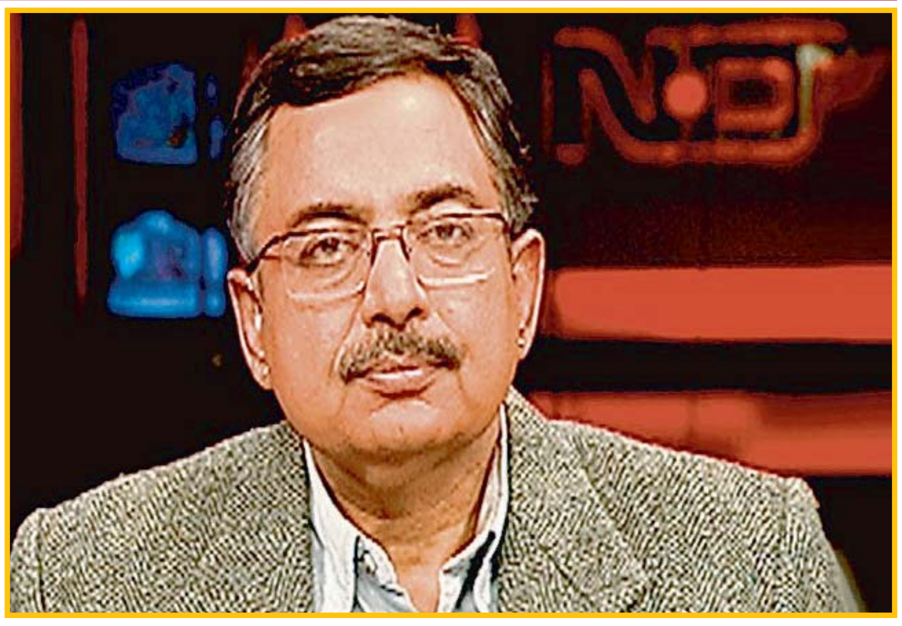

सरकार से असहमति रखने वाले पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मामला देश की सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर दिया है और ऐसा करते समय उसने 1962 के न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया है। इससे पहले भी न्यायालय ने तीन मार्च को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर राजद्रोह का मामला निरस्त करते हुए कहा था कि असहमति वाले विचारों की अभिव्यक्ति को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए में राष्ट्रद्रोह की परिभाषा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, जिससे असंतोष पैदा हो तो यह राष्ट्रद्रोह है। यह दंडनीय अपराध है। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचलने के लिये भारतीय दंड संहिता में इस तरह का कठोर प्रावधान किया था। लेकिन अब तो हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को बोलने और अपनी बात कहने की आजादी प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में कानून की किताब में पुराने स्वरूप में ही बरकरार इस प्रावधान का प्रशासन दुरुपयोग भी करता है। पत्रकार विनोद दुआ के यूट्यूब के एक कार्यक्रम के आधार पर भाजपा नेता ने शिमला में राजद्रोह सहित कई आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी को निरस्त कराने के लिये ही दुआ को उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा। इस मामले में न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने अपने 116 पेज के फैसले में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पत्रकार 1962 की केदार नाथ सिंह प्रकरण की व्यवस्था के अनुरूप संरक्षण का हकदार होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए और धारा 505 के तहत प्रत्येक अभियोजन इन धाराओं के दायरे के अनुरूप ही होना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने विनोद दुआ का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि एक उच्चस्तरीय समिति की मंजूरी के बगैर 10 साल से ज्यादा के अनुभव वाले पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ऐसा करना विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा। जहां तक विनोद दुआ के कार्यक्रम का सवाल था तो न्यायालय का मानना था कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के आधार पर राजद्रोह का कोई मामला नहीं बनता और इसके लिये किसी भी प्रकार का मुकदमा चलाना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में याचिकाकर्ता को प्राप्त मौलिक अधिकारों का हनन होगा। सवाल यह है कि 1962 की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बावजूद नागरिकों, विशेषकर पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मामले दर्ज होते रहे हैं और इसकी चपेट में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसके चंगुल से निकलने के लिये अदालत के चक्कर लगाता रहता है। यह विडंबना ही है कि शीर्ष अदालत की संविधान पीठ की 58 साल पुरानी पुख्ता व्यवस्था के बावजूद आज भी सरकार और उसके नीति निर्धारक नेताओं की कार्यशैली से असहमति व्यक्त करने वाले नागरिकों के खिलाफ किसी न किसी आधार पर राजद्रोह के आरोप में केन्द्र या राज्य सरकारों की ओर से ही दायर होते रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि शीर्ष अदालत ने पहली बार यह व्यवस्था दी है कि सरकार की नीतियों से असहमति व्यक्त करने या इसके खिलाफ आवाज उठाना राजद्रोह के दायरे में नहीं आता बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। इससे पहले भी अनेक मामलों में न्यायालय इस तरह की राय व्यक्त कर चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि कार्यपालिका और नौकरशाही पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। पिछले एक दशक में देश में नागरिकों के खिलाफ राजद्रोह के कम से कम 798 मामले दर्ज हुए।

इनमें से 2010 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के कार्यकाल में राजद्रोह के 279 और इसके बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के शासन में 2014 से 2020 के दौरान 519 ऐसे मामले दर्ज हुए। इसके अलावा, राज्यों में भी इस तरह के मामले दर्ज होते रहे हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने ही दो समाचार चैनलों के खिलाफ अपने ही एक सांसद के आलोचनात्मक बयान प्रसारित करने के मसले पर राजद्रोह के मामले दर्ज किये, जिन पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगायी है। अब सवाल उठता है कि क्या संविधान पीठ की व्यवस्था के तहत अगर प्रत्येक पत्रकार को धारा 124-ए और धारा 505 के तहत संरक्षण प्राप्त होगा तो फिर पत्रकारों के मामले में इन प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिये पुलिस और प्रशासनिक प्राधिकारियों पर दंड की व्यवस्था करना उचित नहीं होगा। इन कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिये पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूक बनाना भी जरूरी है।

दंड के स्वरूप का निर्धारण न्यायालय और सरकार कर सकती है ताकि भविष्य में किसी पत्रकार को अनावश्यक रूप से राजद्रोह के अपराध का आरोपी नहीं बनाया जा सके।

कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी सूरत के हीरा उद्योग निर्यात में हुई 37.78 फीसदी की बढ़ोत्तरी

-लेब्रोन डायमंड में 307 फीसदी तथा रंगीन जेम्स स्टोन में हुई 8.46 फीसदी की वृद्धि

सूरत। गुजरात में कोरोना वायरस मामले दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। सरकार ने सभी सरकारी निजी कार्यालयों में 100 फीसदी कर्मचारियों को काम करने की अनुमति दे दी है। कोरोना की पहली लहर में सूरत के हीरा उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा था। लेकिन दूसरी लहर का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। कोरोना की पहली लहर के दौरान पूरी तरह से पॉलिश किए गए हीरे का उत्पादन पिछले साल मार्च से जुलाई तक रोक दिया गया था। दूसरी लहर में 30 फीसदी कर्मचारियों की कमी के बावजूद हीरा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। गुजरात के सूरत शहर के हीरा उद्योग का दावा है कि कोरोना वायरस की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर का डायमंड इंडस्ट्री पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ है। अप्रैल 2020 की तुलना में 2021 में कटे और पॉलिश किए गए हीरे के निर्यात में 37.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेब्रॉन डायमंड को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। लेब्रोन डायमंड में 307 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरह, रंगीन जेम्स स्टोन में 8.46 फीसदी की वृद्धि देखी जा रही है। जड़े हुए सोने के गहनों में 33.88 फीसदी की तेजी देखी जा रही है। चांदी के आभूषणों में 250.70 फीसदी की तेजी देखी जा रही है। प्लेटिनम ज्वैलरी में 125.72 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। हीरे के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के आभूषण उद्योग में वृद्धि देखी जा रही है, हालांकि, सादे सोने के आभूषणों में गिरावट देखी जा रही है। इस सेक्टर में 59.38 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है।

हुंदै की अलकाजर के लिए बुकिंग शुरू

नई दिल्ली । हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने बुधवार को अपनी आगामी एसयूवी अलकाजर के लिए बुकिंग शुरू की, जिसके इस महीने के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि छह और सात सीटों के विकल्प के साथ आने वाले प्रीमियम एसयूवी को कंपनी के डीलरशिप पर या ऑनलाइन 25,000 रुपए के डाउन पेमेंट के साथ बुक किया जा सकता है। अलकाजर दो-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल के दो इंजन विकल्पों में छह-स्पीड ऑटोमैटिक और छह-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ उपलब्ध होगी।

उबर भारत में 250 इंजीनियरों की भर्ती करेगी

बेंगलुरु। उबर ने कहा कि वह भारत में अपने इंजीनियरिंग और उत्पाद कार्य संबंधी परिचालन में बढ़ोतरी जारी रखने के लिए बेंगलुरु और हैदराबाद में करीब 250 इंजीनियरों की भर्ती करेगी। उबर ने एक बयान में कहा कि इन नियुक्तियों से कंपनी के कैब सेवाओं, आपूर्ति, डिजिटल पेमेंट्स, जोखिम एवं अनुपालन, ग्राहक सेवा, डेटा, सुरक्षा और वित्त प्रौद्योगिकी संबंधी दलों को मजबूती मिलेगी। कंपनी ने बताया कि ये नियुक्तियां हैदराबाद और बेंगलुरु स्थित तकनीकी केंद्रों में की जाएंगी।

विश्वबैंक ने घटाई भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, 2021 में रहेगी 8.3 प्रतिशत

बिजनेस डेस्क:

विश्वबैंक ने मंगलवार को भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 में 8.3 प्रतिशत और 2022 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया। विश्वबैंक ने यह भी कहा है कि कोविड-19 महामारी की अबतक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरूद्धार को नुकसान पहुंचा है। बहुपक्षीय संस्थान ने ग्लोबल इकोनामिक प्रॉस्पेक्ट्स (वैश्विक आर्थिक संभावनाएं) शीर्षक रिपोर्ट के नए संस्करण में कहा है कि भारत में 2020-21 की दूसरी छमाही में खासकर सेवा क्षेत्र में तीव्र पुनरूद्धार की अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। विश्वबैंक ने कहा, ''महामारी की शुरूआत से किसी भी देश के मुकाबले सर्वाधिक भीषण लहर भारत में आयी और इससे आर्थिक पुनरूद्धार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वैश्विक संस्थान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में 2020 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है जबकि 2019 में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2023 में भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली । घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में नरमी आई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 92 रुपये की गिरावट के साथ ही 48,424 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,516 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी भी 414 रुपये नीचे आकर 70,181 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। वहीं पिछले सत्र में चांदी 70,595 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना हल्की बढ़त के साथ ही 1,893 डॉलर प्रति औंस जबकि चांदी 27.65 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर बनी हुई है।

आईएमएफए को मार्च तिमाही में 65 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा

नई दिल्ली:

फेरो-क्रोम उत्पादक इंडियन मेटल्स और फेरो अलॉयज को 31 मार्च 2021 को समाप्त चौथी तिमाही के दौरान 65.49 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध मुनाफा हुआ है। कंपनी की आय बढ़ने से उसे मुनाफा हासिल करने में मदद मिली है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 51.65 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड (आईएमएफए) की कुल आय एक साल पहले के 381.02 करोड़ रुपए से बढ़कर 587.95 करोड़ रुपए हो गई। एक साल पहले की तिमाही में 444.60 करोड़ रुपए की तुलना में कंपनी का खर्च समीक्षाधीन तिमाही में 490.23 करोड़ रुपए रहा है। आईएमएफए प्रति वर्ष 2,84,400 टन की क्षमता के साथ मूल्य वर्धित फेरोक्रोम के क्षेत्र में देश की अग्रणी उत्पादक कंपनी है।

शेयर बाजार में गिरावट

सेंसेक्स 51,941 , निफ्टी 15,635 पर आया

मुंबई।

घरेलू शेयर बाजार बुधवार को नीचे आया है। बाजार में यह गिरावट दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही दिग्गज कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआइ बैंक और एल एंड टी के शेयरों के टूटने और मुनाफावसूली हावी रहने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 333.93 अंक करीब 0.64 फीसदी की गिरावट के साथ ही 51,941.64 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 104.75 अंक तकरीबन 0.67 फीसदी टूटकर 15,635.35 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सबसे अधिक 2 फीसदी का नुकसान एल एंड टी के शेयरों को हुआ। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, मारुति, एक्सिस बैंक और बजाज ऑटो के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गयी। वहीं दूसरी ओर, पावरग्रिड, एनटीपीसी, टाइटन, एचसीएल टेक और एशियन पेंट्स के शेयर लाभ में रहे। बाजार जानकारों के अनुसार वित्त, वाहन और आरआईएल में बिकवाली के दबाव से घरेलू बाजार पर दबाब पड़ा है जिससे वह नीचे आया है। सभी प्रमुख खंडवार सूचकांकों में बिकवाली हावी रही। निवेशकों ने अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण आंकड़े जारी होने से पहले मुनाफावसूली को पर जोर दिया। इससे पहले सुबह विदेशी कोषों की जोरदार आवक के बीच एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे बड़े शेयरों में बढ़त के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी देखी गई। इस दौरान सेंसेक्स 80.72 अंक की तेजी के साथ 52,356.29 पर था। इसी तरह निफ्टी 26.45 अंक बढ़कर 15,766.55 पर पहुंच गया था। सेंसेक्स में सबसे अधिक दो फीसदी की बढ़त ओएनजीसी में हुई। इसके अलावा एसबीआई, सन फार्मा, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, डॉ रेड्डीज और बजाज फिनसर्व भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, बजाज ऑटो और आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट हुई।

किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, खरीफ की फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी

बिजनेस डेस्क:

मोदी सरकार ने किसानों को राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर एमएसपी को अनुमति दे दी है। धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसके साथ ही, बाजरा पर एमएसपी बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल तिल के भाव (एमएसपी) में सबसे अधिक 452 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि तुअर और उड़द के भाव में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी। एमएसपी वह दर होती है जिस दर से सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है।

किसानों के हित के कदम

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों की एमएसपी में 50 फीसदी तक वृद्धि करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 7 साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है।

एमएसपी पर गेहूं की खरीदारी

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक पूरे देश से इस साल करीब 416.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 371.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस बार **MSP** पर 12.14 प्रतिशत ज्यादा खरीद हुई है। गेहूं खरीद में टॉप 5 राज्यों में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। कुल खरीद में 132.1 लाख मीट्रिक टन के साथ सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां 128.08 एलएमटी की खरीद हुई है जबकि 84.93 एलएमटी के साथ तीसरे नंबर पर हरियाणा और 45.78 एलएमटी के साथ उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है।

कैबिनेट ने रेलवे के लिए 5 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे को संचार और सिग्नलिंग प्रणाली में सुधार के लिए 700 मेगाहट्र्ज बैंड में 5 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इससे रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। करीब 25,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। रेलवे अभी अपने संचार नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर पर निर्भर है लेकिन नए स्पेक्ट्रम के आवंटित होने के बाद वह तेज रफ्तार वाले रेडियो का उपयोग कर सकेगा। जावड़ेकर ने कहा कि इस आवंटन से रेलवे के संचार और सिग्नलिंग नेटवर्क दोनों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने ट्वीट किया, कैबिनेट ने भारतीय रेल को स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा तथा सुरक्षा सेवाओं के लिए 700 मेगाहट्र्ज बैंड में पांच मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी, इस पर अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है, यह परियोजना अगले पांच वर्षों में पूरी होगी।

बीते पांच माह में 70 प्रतिशत बढ़ गया भारत-चीन के बीच व्यापार

बीजिंग।

गलवान घाटी में बीते साल हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ा, लेकिन इसका असर दोनों देशों के व्यापार पर बिलकुल भी नहीं पड़ा है। संभवतः इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस है, लेकिन आंकड़ों में देखें तो भारत और चीन के बीच इस साल के शुरुआती पांच महीनों में व्यापार पिछले साल की तुलना में 70 फीसदी तक बढ़ गया है। हालांकि, यह आंकड़े चीन की ओर से पेश किए गए हैं, लेकिन भारतीय आंकड़े देखें तो दोनों देशों में व्यापार 55.83 फीसदी बढ़ गया है। हालांकि, दोनों देशों के आंकड़ों में फर्क की वजह अभी तक पता नहीं लग सकी है। दोनों ही देश डॉलर में व्यापार करते हैं। चीनी मीडिया ने इसे 'शानदार बढ़ोतरी' बताते हुए कहा है कि सीमा पर तनाव के बावजूद यह दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में लचीलेपन का संकेत है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, 2021 के पहले पांच महीनों में चीन और भारत के बीच व्यापार 70.1 फीसदी बढ़ा है। जनवरी से मई के बीच सालाना आंकड़े देखें तो चीन का भारत को निर्यात 64.1 फीसदी बढ़ा है, वहीं आयात में 90.2 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। वहीं, भारत के आंकड़ों के मुताबिक, चीन से आयात में 59.13 फीसदी की बढ़त हुई है और अब यह 33.49 अरब डॉलर यानी 2441.42 अरब रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चीन को निर्यात में भी 46.09 फीसदी वृद्धि हुई है और अब यह 10.41 अरब डॉलर यानी 758.89 अरब रुपये तक पहुंच गया है। इस अवधि में दोनों देशों के बीच हुआ व्यापार चीन के किसी भी अन्य देश से व्यापार की तुलना में ज्यादा है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार चीन का भारत को निर्यात अप्रैल से मई के बीच तेजी से बढ़ा है। संभवतः ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था और उसने चीन से बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य उपकरण मंगवाए थे। भारत और चीन के बीच बीते साल यानी 2020 में व्यापार 9.1 प्रतिशत कम हो गया था। हालांकि, चीन तब भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था। ये आंकड़े कैलेंडर वर्ष के लिए थे। भारत में अप्रैल से मार्च को वित्त वर्ष माना जाता है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2020-21 के बीच चीन को भारत की ओर से किए जा रहे निर्यात में 27.53 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीनी आयात में 0.07 फीसदी की कमी देखी गई है। इस वित्त वर्ष में भारत और चीन के बीच कुल व्यापार 86.4 अरब डॉलर का रहा।

जीवन बीमा कंपनियों की मई में पहले साल की प्रीमियम आय में 5.6 प्रतिशत गिरावट

नई दिल्ली:

जीवन बीमा कंपनियों की नए कारोबार से प्रीमियम आय मई 2021 में 5.6 प्रतिशत घटकर 12,976.99 करोड़ रुपए रही। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के आंकड़ों के अनुसार देश में 24 जीवन बीमा कंपनियों की नए कारोबार से मिलने वाली पहले साल की प्रीमियम आय एक साल पहले इसी माह में 13,739 करोड़ रुपए थी।

इसमें देश की सबसे बड़ी और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की प्रीमियम आय मई 2021 में 12.4 प्रतिशत गिरकर 8,947.64 करोड़ रुपए रही। एक साल पहले मई 2020 में यह 10,211.53 करोड़ रुपए थी। आंकड़ों के अनुसार शेष 23 निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की नए कारोबार से प्रीमियम आय मई 2021 में 14.2 प्रतिशत बढ़कर 4,029.35 करोड़ रुपए रही जो एक साल पहले इसी महीने में 3,527.48 करोड़ रुपए थी। वही अप्रैल-मई के दौरान जीवन बीमा कंपनियों की नए कारोबार से प्रीमियम आय लगभग 11 प्रतिशत बढ़कर 22,715.78 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 20,466.76 करोड़ रुपए थी।

इंफोसिस के को-फाउंडर ने भारत में किया क्रिप्टोकरेंसी का समर्थन

नई दिल्ली ।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क समेत दुनियाभर के तमाम दिग्गज और अरबपति क्रिप्टोकरेंसी में निवेश की सलाह दे रहे हैं। इस बीच अब इंफोसिस के को-फाउंडर और चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी का समर्थन किया है। उन्होंने भारतीयों से डिजिटल करेंसी को बतौर संपत्ति की तरह उपयोग करने की सलाह दी है। एक इंटरव्यू में नीलेकणि ने कहते हैं, जैसे आपके पास सोने या रियल एस्टेट में कुछ संपत्ति है, वैसे ही आप अपनी कुछ संपत्ति क्रिप्टो में रख सकते हैं। मुझे लगता है कि क्रिप्टो के लिए एक स्टोर वैल्यू के रूप में काम करता है लेकिन निश्चित रूप से लेनदेन के अर्थ में नहीं है। नीलेकणि ने कहा कि लोगों और व्यवसायों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर बाजार में टैप करने की अनुमति देने से क्रिप्टोकरेंसी रखने वाले लोग भारत की अर्थव्यवस्था में अपना पैसा लगा सकते हैं। बुधवार को बिटकॉइन समेत प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी में फिर से गिरावट आई। 9 जून को सुबह आईएसटी पर बिटक्वाइन 3.22 फीसदी गिरकर 32,592.33 दो सप्ताह के निचले स्तर 32,592.33 पर आ गई है। बिटकॉइन की कीमत पेशेवर निवेशकों की दिलचस्पी से बढ़ी है।

जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ईथर 5.82 फीसदी घटकर 2,446.88 डॉलर रह गई। वहीं डॉगक्वाइन की कीमत जनवरी में एक पैसे से भी कम से बढ़कर मई में लगभग 70 सेंट हो गई। यह वर्तमान में लगभग 31 सेंट पर कारोबार कर रहा है।

जून के पहले हफ्ते में निर्यात 52.39 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली ।

वाणिज्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग तथा पेट्रोलियम उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी मांग के चलते भारत का निर्यात इस महीने के पहले सप्ताह के दौरान 52.39 प्रतिशत बढ़कर 7.71 अरब डॉलर हो गया। आयात भी 1-7 जून के दौरान लगभग 83 प्रतिशत बढ़कर 9.1 अरब डॉलर हो गया। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान इंजीनियरिंग का निर्यात 59.7 प्रतिशत बढ़कर 74.11 करोड़ अमरीकी डालर, रत्न और आभूषण का निर्यात 96.38 प्रतिशत बढ़कर 29.78 करोड़ अमरीकी डालर और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 69.53 प्रतिशत बढ़कर 53.06 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया। हालांकि, समीक्षाधीन अवधि में लौह अयस्क, तिलहन और मसालों के निर्यात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। जून के पहले सप्ताह में पेट्रोलियम और कच्चे तेल का आयात 135 प्रतिशत बढ़कर 1.09 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोती तथा कीमती पत्थरों के आयात में भी बढ़ोतरी हुई।इस दौरान अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, जबकि चीन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से आयात तेजी से बढ़ा।

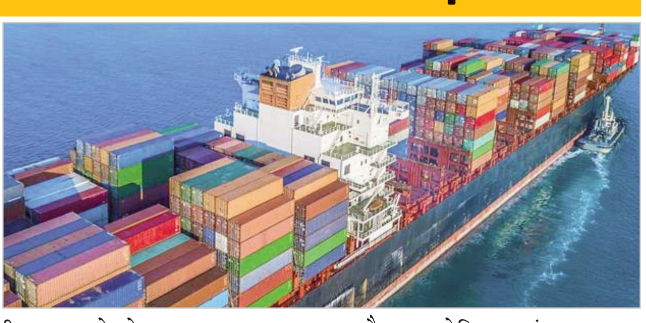

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जडेजा, अश्विन और साउदी ऊपर आये

दुबई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। जडेजा के 386 अंक हैं। वहीं स्टोक्स 385 अंक लेकर साथ तीसरे नंबर पर खिसक गये हैं। भारत के आर अश्विन ऑलराउंडर रैंकिंग में चौथे नंबर पर बरकरार हैं। उनके 353 अंक हैं। वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर नंबर एक पर पहुंच गये हैं। वहीं गेंदबाजों की आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन दूसरे नंबर पर हैं। अश्विन के 850 अंक हैं। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस बरकारार हैं। उनके 908 अंक हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी को भी इसमें फायदा हुआ है। साउदी इसी के साथ ही गेंदबाजों की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पहले वो 6 वें नंबर पर थे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन से उन्हें तीन पायदान का लाभ मिला है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में साउदी ने सात विकेट लिए थे। उनके 838 अंक हैं। चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड के नील वैगनर जबकि पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इस छठे नंबर पर हैं।

सिटसिपास ने मेदवेदेव को हराया

सेमीफाइनल में जेवरेव से भिड़ेंगे

पेरिस ।

स्टेफनोस सिटसिपास और अलेक्सांद्र जेवरेव ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में जगह बनायी जहां ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इन दोनों को भविष्य का स्टार माना जाता है। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच 2008 के सेमीफाइनल के बाद यह पहला अवसर है जबकि रोलां गैरां पर अंतिम चार में दो युवा खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करेंगे। पांचवी वरीयता प्राप्त सिटसिपास ने दूसरे वरीय डेनिल मेदवेदेव को 6-3, 7-6 (3), 7-5 से हराकर चौथी बार किसी ग्रैंडस्लैम के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उन्हें केवल दूसरे सेट में संघर्ष करना पड़ा जब 5-4 के स्कोर पर मेदवेदेव दो सेट प्वाइंट का फायदा नहीं उठा पाये थे। पिछले साल यूएस ओपन के फाइनल में जगह बनाने वाले जेवरेव ने 46वी रैंकिंग के अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को 6-4, 6-1, 6-1 से पराजित किया। यह तीसरा अवसर है जबकि जेवरेव ग्रैंडस्लैम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। यूनान के सिटसिपास 22 वर्ष के जबकि जर्मनी के जेवरेव 24 वर्ष के हैं। इन दोनों ने इस साल लाल बजरी पर मास्टर्स 1000 खिताब जीता था। पुरुष वर्ग के दो अन्य क्वार्टर फाइनल जोकोविच और मैटियो बेरेटिनी तथा 13 बार के चैंपियन नडाल और डिएगो श्वार्जमैन के बीच खेले जाएंगे। महिला वर्ग में रूस की 31वीं वरीय एनस्तेसिया पावलिचेनकोवा और स्लोवानिया की 85वी रैंकिंग की तमारा जिदानसेक ने पहली बार ग्रैंडस्लैम सेमीफाइनल में जगह बनायी। पावलिचेनकोवा इससे पहले छह बार ग्रैंडस्लैम क्वार्टर फाइनल में हारी थी लेकिन मंगलवार को वह युगल में अपनी जोड़ीदार इलेना रिबाकिना को एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-7 (2), 6-2, 9-7 से हराने में सफल रही। जिदानसेक ने 33वीं रैंकिंग की पाउल बाडोसा को 7-5, 4-6, 8-6 से हराया।

अभी फुटबॉल से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं : छेत्री

नयी दिल्ली,

लंबे समय से संन्यास की अटकलों से बेपरवाह भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने बुधवार को कहा कि वह निकट भविष्य में खेल को अलविदा कहने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी अच्छे प्रदर्शन की ललक बरकरार है हालांकि कई बार प्रेरणा बनाये रखना मुश्किल हो जाता है । दोहा में बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर में दो शानदार गोल करके भारत को 2 . 0 से जीत दिलाने वाले 36 वर्ष के छेत्री ने दीर्घकालिन लक्ष्य तय करने से इनकार किया । उन्होंने दोहा से आनलाइन बातचीत में कहा,'' मैं अभी संन्यास के बारे में नहीं सांच रहा । मैं अहंकारी नहीं हूं । मैं अपने खेल का मजा ले रहा हूं । मैं पहले से ज्यादा फिट हूं । मैं 36 साल का हूं लेकिन देश के लिये खेलने का जोश और जुनून बरकरार है ।'' छेत्री ने कहा ,'' लोग पूछते हैं कि मैं 36 साल का हूं और कितने समय तक खेलूंगा । मैं इसकी परवाह नहीं करता । लोगों की अपनी राय होती है और

मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं । जिस दिन मैं अपने खेल का मजा नहीं ले सकूंगा, उस दिन खुद खेल को अलविदा कह दूंगा ।'' उन्होंने कहा कि उम्र के साथ अपने खेल के बारे में वह ज्यादा समझने लगे हैं और उन्हें पता है कि वह कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं । उन्होंने कहा ,'' कठिन बात प्रेरणा बनाये रखना है ।उम्र के साथ और उपब्धियां हासिल करने के बाद वह कम हो जाती है ।''

नार्वे की लेटिजनबेड ने ओलंपिक ट्रायल्स में नया विश्व रिकार्ड बनाया

हेंजेलो। नार्वे की लेटिजनबेड गिडे ने नीदरलैंड में आयोजित इथोपियाई ओलंपिक ट्रायल्स में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में 29 मिनट 1.03 सेकेंड का समय निकालकर नया विश्व रिकार्ड बनाया है। सिगी गेब्रेसेलामा 30 मिनट 06.01 सेकेंड के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं इससे पहले नीदरलैंड की सिफान हसन ने इसी ट्रैक पर दो दिन पहले एक रिकार्ड बनाया था। हसन ने फैनी ब्लैंकर्स कोइन खेलो में रिकार्ड बनाया था जिसके समय में गिडे ने 5.79 सेकेंड का सुधार किया।सिफान ने दो दिन पहले पांच साल पुराना रिकार्ड तोड़ा था। उन्होंने इथोपिया की अलमाज अयानास के रियो ओलंपिक 2016 में बनाए गए रिकार्ड से 10.63 सेकेंड कम समय निकाला था। गिडे इस प्रकार से नार्वे की इंग्रिड क्रिस्चियनसेन के बाद पहली महिला धाविका बन गयी हैं जिनके नाम पर 5000 और 10000 मीटर दौड़ का विश्व रिकार्ड है। क्रिस्चियनसेन ने 1986 से 1993 के बीच यह रिकार्ड बनाया था। गिडे ने बाद में कहा कि मुझे विश्व रिकार्ड बनाने की उम्मीद थी।

सुशील को खानी पड़ेगी जेल की रोटी

स्पेशल डाइट-फूड सप्लीमेंट्स की याचिका खारिज

नई दिल्ली ।

दो बार के ओलम्पिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जेल में अपने लिए स्पेशल डाइट और फूड सप्लीमेंट की मांग वाली याचिका को रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुशील की मांग को खारिज करते हुए कहा कि जेल में जो जरूरी चीजें हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार का अब नया ठिकाना मंडोली जेल का 15 नम्बर जेल है। अदालत के सुशील को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिए जाने के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और उसे लेकर मंडोली जेल पहुंची। कोरोना को देखते हुए फिलहाल सुशील को जेल नंबर 15 में ही अगले 14 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा। इस दौरान वो अन्य कैदियों से पूरी तरह अलग रहेगा। जेल के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार जेल पहुंचने के बाद सुशील को जेल का खाना दिया गया, लेकिन उसने खाना खाने से मना कर दिया। इस मामले में सुशील के साथ शामिल रहे सभी अन्य आरोपियों को भी इसी जेल में रखा गया है। जेल सूत्रों का कहना है कि जेल पहुंचने पर सुशील काफी डरा हुआ था। दरअसल सुशील गैंगस्टरों से डर की वजह से जेल जाने से कतरा रहा था और पुलिस के सामने रो रहा था। जेल अधिकारियों का कहना है कि सुशील को तमिलनाडु पुलिस की सुरक्षा में रखा जाएगा और उसपर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी।

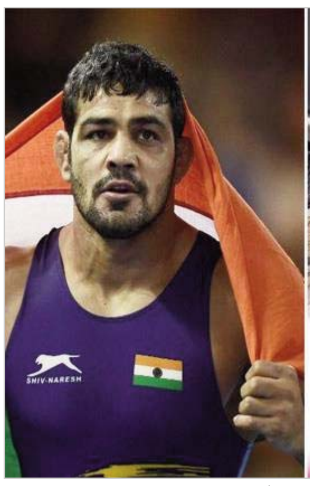

संक्षिप्त समाचार

आईएसएल के नए नियम : क्लबों को न्यूनतम 7 भारतीय खिलाड़ी उतारने होंगे

मुंबई । इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल टूर्नामेंट के 2021-22 सत्र में स्थानीय खिलाड़ियों के मैदान में प्रतिनिधित्व में इजाफा होगा और नए नियमों के तहत क्लबों को न्यूनतम सात भारतीय खिलाड़ियों को मैदान पर उतारना होगा जो पिछले सत्र के छह की तुलना में एक अधिक है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्थान में इजाफे का मतलब है कि विदेशी खिलाड़ियों के लिए टीम में अब एक स्थान कम होगा और एक समय में अधिकतम चार विदेशी खिलाड़ी ही मैदान पर उतर सकते हैं। आईएसएल ने कहा- इंडियन सुपर लीग 2021-22 सत्र में मैदान पर खेल रही एकादश में भारतीय खिलाड़ियों की संख्या में इजाफा होगा क्योंकि फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (एफएसडीएल) के नए कोच एवं खिलाड़ी चयन दिशानिर्देशों के अनुसार क्लबों के लिए हर समय न्यूनतम सात भारतीय खिलाड़ियों को मैदान पर उतारना अनिवार्य होगा। वर्ष 2014 में खेले गए पहले टूर्नामेंट में अधिकतम छह विदेशी खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने की स्वीकृति थी। लीग में भारतीय खिलाड़ियों के स्थानों में लगातार इजाफा हुआ है। आईएसएल 2017-18 से न्यूनतम छह भारतीय खिलाड़ियों का मैदान पर होना अनिवार्य था जिसे अगले सत्र से बढ़ाकर सात कर दिया गया है। विदेशी खिलाड़ियों की अधिकतम सीमा को चार तक सीमित करना एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) की क्लब प्रतियोगिताओं के नियमों के अनुसार है। इस बदलाव के बाद क्लब अधिकतम छह विदेशी खिलाड़ियों से अनुबंध कर सकते हैं जिसमें से एक एएफसी सदस्य देश का होना अनिवार्य है। क्लबों के पास लीग से स्वीकृत खिलाड़ियों के बीच विदेशी मार्की खिलाड़ी से अनुबंध का विकल्प भी होगा। इस सत्र से क्लब को दो की जगह न्यूनतम चार डेवलपमेंट (उभरते हुए युवा खिलाड़ी) खिलाड़ियों से अनुबंध करना होगा और इनमें से कम से कम दो मैदान पर उतरेंगे। क्लब इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी के चोटिल होने की दशा में विकल्प की मांग कर सकता है जो अधिकतम पंजीकृत 35 खिलाड़ियों से अलग होगा। आगामी सत्र के लिए टीम की वेतन सीमा को 16 करोड़ 50 लाख रुपये बरकरार रखा गया है।भारतीय फुटबॉल की ट्रांस्फर विंडो बुधवार से शुरू होगी जिससे क्लबों को अपनी पसंद के खिलाड़ियों से अनुबंध का मौका मिलेगा।

30 जुलाई से शुरू होगी श्रीलंकाई प्रीमियर लीग

कोलंबो । श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) के अनुसार श्रीलंकाई प्रीमियर लीग (एलपीएल) टी-20 टूर्नामेंट का दूसरा सत्र अगले माह 30 जुलाई से 22 अगस्त के बीच जैव-सुरक्षित वातावरण (बायो-बबल) में खेला जाएगा। एसएलसी यह बताना चाहता है कि पहले की घोषणा के अनुसार लंका प्रीमियर लीग का दूसरा सत्र जुलाई और अगस्त 2021 के दौरान आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 30 जुलाई से 22 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र (2020) को बायो-बबल में खेला गया था। एलपीएल के दूसरे सत्र के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की योजना स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर बनाई जाएगी। इसके पहले सत्र में भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान, मुनाफ पटेल और सुदीप त्यागी भी शामिल हुए थे।

ब्राजील जीता, अर्जेंटीना ने आखिर में गोल गंवाकर खेला ड्रा

साओ पाउलो ।

ब्राजील ने पराग्वे को 2-0 से हराकर अपनी लगातार छठी जीत के साथ दक्षिण अमेरिका से विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालीफाई करने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए। ब्राजील अब दूसरे नंबर पर काबिज अर्जेंटीना से छह अंक आगे हो गया है जिसने दो गोल की बढ़त के बावजूद कोलंबिया से 2-2 से ड्रा खेला। नेमार और लुकास पाक्वेटा ने ब्राजील की तरफ से गोल किए। यह ब्राजील की विश्व कप क्वालीफायर्स में पराग्वे पर पिछले 35 वर्षों में पहली जीत है। इससे पहले मिगुएल बोर्जा ने कोलंबिया की तरफ से दूसरे हाफ के इंजुरी टाइम के आखिरी सेकेंड में गोल करके अर्जेंटीना की जीत की उम्मीदों पर पानी फेरा। यह दक्षिण अमेरिकी क्वालीफाईंग के सर्वश्रेष्ठ मैचों में एक था। बरानक्विला के मेट्रोपोलिटन स्टेडियम में इस मैच को देखने के लिये 10,000 दर्शक उपस्थित थे। दक्षिण अमेरिकी क्वालीफायर्स से चार टीमें स्वतः ही कतर में 2022 में होने वाले विश्व कप में जगह बनाएंगी जबकि पांचवें स्थान की टीम अंतरमहाद्वीपीय प्लेआफ में भाग लेगी। अभी ब्राजील 10 टीमों की प्रतियोगिता में 18 अंक लेकर शीर्ष पर है। उसके बाद अर्जेंटीना (12), इक्वाडोर (नौ) उरुग्वे और कोलंबिया (दोनों आठ) का नंबर आता है। उरूग्वे और नौवें स्थान के वेनेजुएला के बीच मैच गोल रहित बराबरी पर छूटा। पेरू ने एक अन्य मैच में इक्वाडोर को 2-1 से हराया। पेरू की यह इस बार के विश्व कप क्वालीफायर्स में पहली जीत है।

ओलिम्पिक में पदक जीतने का यकीन है : पूजा रानी

नई दिल्ली :

एशियाई चैम्पियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण जीतने के बाद आत्मविश्वास से ओतप्रोत मुक्केबाज पूजा रानी (75 किलो) ने बुधवार को कहा कि उन्हें टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का पूरा यकीन है। पूजा ने चंद रोज पहले दुबई में एशियाई चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने कहा कि मैं ओलिम्पिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी और बाकी ईश्वर की मर्जी । मुझे ओलिम्पिक में पदक जीतने का यकीन है। उन्होंने कहा कि मैं ओलिम्पिक की तैयारी से खुश हूं। एशियाई चैम्पियनशिप में पदक से मेरा आत्मविश्वास और उम्मीद बढी है। हरियाणा के भिवानी की रहने वाली इस मुक्केबाज को चीन, वेल्स, नीदरलैंड और रूस के मुक्केबाजों से ओलिम्पिक में चुनौती मिलने की उम्मीद है। एम सी मैरीकोम समेत भारत की 4 महिला मुक्केबाजों ने ओलिम्पिक के लिए क्वालीफाई किया है। पूजा ने कहा कि हम चारों 15 जून को अभ्यास के लिए इटली जा रहे हैं। वहां हम अपने अभ्यास जोड़ीदारों के साथ अभ्यास करेंगे। ओलिम्पिक से पहले कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है तो इससे फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना के टीके का पहला डोज दो जून को लगा है और दूसरा डोज इटली से लौटने के बाद लगेगा।

यूरो 2020 से पहले स्वीडन के दो खिलाड़ी कोरोना संक्रमित

गोटेनबर्ग । यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप-यूरो 2020 के लिए स्वीडन की टीम में शामिल दो खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। टीम ने टूर्नामेंट शुरू होने से तीन दिन पहले इसकी जानकारी दी। युवेंटस के विंगर देजा कुलुसेवस्की ने स्वीडन की चिकित्सा टीम को बीमारी से जुड़े लक्षणों के बारे में बताया जिसके बाद उनका परीक्षण करने पर वहां पॉजिटिव आया। कुलुसेवस्की स्टाकहोम में ही हैं जबकि बाकी टीम गोटेनबर्ग पहुंच गयी। गोटेनबर्ग में पहले अभ्यास मैच से पूर्व बोलोग्ना की तरफ से खेलने वाले मिडफील्डर मैटियास स्वानबर्ग टीम के चिकित्सक आंद्रेस वेलेंटाइन के पास जाकर, उनका परीक्षण कराया गया जो कि पॉजिटिव रहा। स्वानबर्ग को टीम होटल में ही अलग थलग कर दिया गया है। इन दोनों के स्थान पर अभी किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया गया है। यूरो 2020 शुक्रवार से शुरू होगा जिसमें पहला मैच मेजबान इटली और तुर्की के बीच खेला जाएगा।

स्पेन की युवा टीम ने लिथुवानिया को हराया, फ्रांस भी जीता

लंदन ।

स्पेन की युवा खिलाड़ियों से सजी टीम ने यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के अभ्यास मैच में लिथुवानिया को 4-0 से करारी शिकस्त दी। स्पेन ने कप्तान सर्जियो बासक्वेट के कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद मैच के लिए अपनी अंडर-21 टीम के खिलाड़ियों से टीम तैयार की। इस मैच के लिए जिन 20 खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया था उनमें से 19 खिलाड़ी कभी सीनियर टीम में नहीं खेले थे। इस मैत्री मैच को सीनियर स्तर पर अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। यह कोच लुइ डि ला फुएंटे का भी मुख्य टीम के साथ आधिकारिक तौर पर पहला मैच था। डि ला फुएंटे ने शुरुआती एकादश में 10 नये खिलाड़ियों को रखा। ब्रायन गिल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें सीनियर टीम की तरफ से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव था। इससे पहले स्पेन ने सीनियर स्तर पर 1941 में 10 खिलाड़ियों को पदार्पण का मौका दिया था। वेलेंसिया के डिफेंडर ह्यूगो गुइलमोन ने तीसरे मिनट में ही स्पेन की तरफ से गोल किया जबकि ब्राहिम डियाज ने 24वें मिनट में बढ़त दोगुनी कर दी। जुआन मिरांडा ने दूसरे हाफ के नौवें मिनट में तीसरा जबकि स्थानापन्न जावी पाउडो ने 73वें मिनट में गोल करके पदार्पण करने वाले खिलाड़ियों के लिए इसे यादगार रात बना दिया। इस बीच फ्रांस ने एक अन्य मैच में बुल्गारिया को 3-0 से हराया लेकिन इस मैच में उसके स्टार खिलाड़ी करीम बेंजेमा के चोटिल होने से यूरोपीय चैंपियनशिप से पहले उसकी चिंताएं बढ़ गई। बेंजेमा केवल 41 मिनट तक ही मैदान पर रह पाये। बेंजेमा की जगह मैदान पर उतरे ओलिवर गिरोड ने आखिरी सात मिनट में दो गोल किये। उनसे पहले एंटोनी ग्रीजमैन ने 29वें मिनट में पहला गोल किया था। अन्य अभ्यास मैचों में चेक गणराज्य ने अल्बानिया को 3-1 से हराया, आइसलैंड और पोलैंड का मैच 2-2 से जबकि हंगरी और आयरलैंड का मैच गोलरहित बराबर छूटा।

क्रोएशिया दौरे से अभ्यास का अच्छा अवसर मिला : मनु भाकर

जागरेब । भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर के अनुसार आगामी टोक्यो ओलंपिक से पहले क्रोएशिया दौरे से सभी निशानेबाजों को बेहद लाभ हुआ है। मनु ने कहा कि इस दौरे से जिस प्रकार के अभ्यास का अवसर मिला ओलंपिक के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। भारतीय निशानेबाज ओसियेक में आमंत्रित टीम के रूप में यूरोपीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद अब जागरेब में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये निशानेबाज आसियेक में 22 जून से तीन जुलाई तक होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप में भी चुनौती पेश करेंगे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण भारत में शिविर का आयोजन संभव नहीं था और ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने क्रोएशिया दौरे का आयोजन किया था। मनु ने कहा कि इस दौरे से काफी मदद मिली। साथ ही कहा कि इस दौरे में हमारा, हमारे स्वास्थ्य और फिटनेस जरूरतों का अच्छी तरह ध्यान रखा गया और सबसे महत्वपूर्ण हमें बेहद अच्छी निशानेबाजी रेंज में ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है और साथ ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका भी। उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि ओलंपिक खेलों से पहले इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। इस पदक दावेदार निशानेबाज ने कहा कि वह अपेक्षाओं के बोझ तले दबने से बचना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हूं। मैं इसके अलावा किसी चीज के बारे में नहीं सोच रही, बस खेलों में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान है।

पहाड़ों की चादर ओढ़े मेघालय

शिलांग भारत के उत्तर–पूर्वी राज्य मेघालय की राजधानी है। भारत के पूर्वोत्तर में बसा शिलांग हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। इसे भारत के पूरब का स्कॉटलैण्ड भी कहा जाता है। पहाड़ियों पर बसा छोटा और खूबसूरत शहर पहले असम की राजधानी था। असम के विभाजन के बाद मेघालय बना और शिलांग वहां की राजधानी। लगभग 1695 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस शहर में मौसम हमेशा खुशगवार बना रहता है। मानसून के दौरान जब यहां बारिश होती है, तो पूरे शहर की खूबसूरती और निखर जाती है और शिलांग के चारों तरफ के झरने जीवंत हो उठते है।

शिलांग के अधिकांश लोग खासी नामक जनजाति के हैं। इस जनजाति? के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। खासी जनजाति के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इस जनजाति में महिला को घर का मुखिया माना जाता है। जबकि भारत के अधिकांश परिवारों में पुरुष को प्रमुख माना जाता है। इस जनजाति में परिवार की सबसे बड़ी लड़की को जमीन जायदाद की मालकिन बनाया जाता है। यहां मां का उपनाम ही बच्चे अपने नाम के आगे लगाते हैं।

चेरापुंजी भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मेघालय का एक शहर है। यह शिलांग से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान दुनिया भर में मशहूर है। हाल ही में इसका नाम चेरापूंजी से बदलकर सोहरा रख दिया गया है। वास्तव में स्थानीय लोग इसे सोहरा नाम से ही जानते हैं। यह स्थान दुनियाभर में सर्वाधिक बारिश के लिए जाना जाता है। इसके नजदीक ही नोहकालीकाई झरना है, जिसे पर्यटक जरूर देखने जाते हैं। यहां कई गुफा भी हैं, जिनमें से कुछ कई किलोमीटर लम्बी हैं। चेरापूंजी बांगलादेश सीमा से काफी करीब है, इसलिए यहां से बांगलादेश को भी देखा जा सकता है।

ऐसा नहीं है की जब भी आप को अपनी छुट्टियाँ मज़ेदार बनानी हो आप गोवा या किसी हिल स्टेशन की ओर निकल पड़ें। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी आपको बेहद सुकून और शांति के अहसास का आनंद मिल सकता है । जी हाँ, अगर आप को माइंड रिफ्रेश करना हो और कुछ दिनों के लिए आप भाग दौड़ से दूर स्ट्रेस फ्री मूड में रहना चाहते हैं तो मेघालय से अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती।

मेघालय यानि 'बादलों का घर', जिसका नाम ही इतना ताज़गी भरा हो सोचिये ज़रा वो जगह भी कितनी शानदार होगी। मेघालय में जो रुहानी राहत और मानसिक शांति मिलती है वो तो बस अनमोल ही है। यहाँ की मनोरम वादियाँ देख कोई भी इसकी खूबसूरती का कायल हुए बिना नहीं रह पायेगा। मेघालय की प्राकृतिक सुन्दरता ही है जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ का वातावरण भी बहुत ही मनमोहक और ताज़गी से भरपूर होता है। बारिश के दिनों में तो वर्षा से भरे बादलों के बीच मेघालय की पहाड़ियां बहुत दिल लुभावनी दिखाई देती हैं।

मेघालय में घूमने के लिए बहुत सी शानदार जगहें हैं जहाँ प्रकृति की असली सुन्दरता बहुत ही भव्य रूप में नज़र आती है।

शीतल शिलॉंग

मेघालय का कैपिटल शिलॉंग पर्यटकों का सबसे महत्वपूर्ण टूरिज्म डेस्टिनेशन है। और भला ऐसे कैसे हो सकता है कि आप भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जायें और शिलॉंग न देखें । शिलॉंग जाये बिना तो आपके घूमने का मज़ा अधुरा ही रह जायेगा। शिलॉंग की लाजवाब खूबसूरती और यहाँ की ऊँची-ऊँची पहाड़ियां आप का दिल चुरा लेंगी। शिलॉंग जाने के लिए बारिश का मौसम बहुत ही उत्तम होता है। शिलॉंग की किसी पर्वत चोटी पर खड़े हो कर पूरे शहर का अद्वितीय नज़ारा लिया जा सकता है। शिलॉंग में अनेक मनोरम स्थल हैं जिन में वार्ड लेक, लेडी हैदरी पार्क, पोलो ग्राउंड और मिनी चिड़ियाघर प्रमुख हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्द है एलीफैंट वाटर फॉल जो बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही यहाँ पर लोग एयर बैलून का भी पूरा लुत्फ़ उठाते हैं।

चंचल चेरापूंजी

चेरापूंजी नाम सुनते ही बचपन में पढ़ा जियोग्राफी का वो चैप्टर याद आ जाता है ना जिसमे हमने पढ़ा था 'चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है'। सोचिये कितना रोमांच भरा होगा ऐसी जगह को हकीकत में देखना । चेरापूंजी पर्यटकों का फेवरेट स्पॉट है। चेरापूंजी में माकडॉक और डिमपेप घाटी का दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। चेरापूंजी की बारिश की बूंदे तन-मन को ऐसे भिगो देंगी की दिल ताज़गी से भर उठेगा। चेरापूंजी का सबसे आकर्षक स्थान है नोहकलिकाई झरना। हजारों फीट ऊपर से गिरता यह दूधिया सफ़ेद झरना बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत है। इसके अलावा चेरापूंजी का माउलंग सीम पीक एक ऐसा स्थान है जो यात्रियों के लिए रहस्य, रोमांच, साहस और सौंदर्य से भरा हुआ है। दूर एक हज़ार मीटर ऊंचाई से गिरता झरना, घने वृक्षों से घिरा जंगल, बादलों के पास बसा बांग्लादेश यहां से दिखाई देता है।

मेघालय में पाई जाने वाली गारो पहाडियों में तो मानसून के मौसम में घूमने का मज़ा दोगुना हो जायेगा। मानसूनी सीजन के वक्त यहाँ बादल हमेशा बने रहते हैं। खासी और जेंतिया पहाड़ी की ऊंचाई पर एक विशेष प्रकार का मौसम रहता है, जिसमें हल्की ठंडक ह्द्द्ढ्ह्ल्द्ढ है। विंटर में यहां तेज़ सर्दी पड़ती है। इसके साथ ही रामकृष्ण का मंदिर, नोखालीकाई वॉटर फॉल, वेल्श मिशनरियों की दरगाहें, ईको पार्क, डबल ड्रेकर रूट ब्रिज और चेरापूंजी मौसम विभाग वैधशाला देखने लायक स्थान हैं। चेरापूंजी में होने वाली तेज़ बारिश से यहाँ की चट्टानों में दरार पड़ गई है और सभी ढलानों पर झरने का दृश्य बेहद मनोरम है।

मेघालय देश के उत्तरी पूर्व क्षेत्र का खूबसूरत राज्य है जिसे देख कर लगता हैं मानो इसने पहाड़ की चादर ओढ़ रखी हो। इस राज्य का एक तिहाई हिस्सा घने जंगलों से भरा है। इस राज्य को पूरब का स्काटलैंड कहा जाता है। यहां पूरे देश के मुकाबले बहुत ज्यादा बारिश होती है।

मेघालय बायोडाइवरसिटी यानी जैविक विविधता से भरपूर है। यहां पौधे, जीव-जन्तु और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। मेघालय में खेती में प्राथमिकता दी गई है। यहां की मुख्य फसलें हैं- केला, मक्का, अनानास, आलू और चावल। मेघालय की शिलांग चोटी को यहां के निवासी भगवान का निवास स्थल मानते हैं।

पर्यटकों का यहां हर समय तांता लगा रहता है। इस राज्य की खूबसूरती और इसके मनमोहक दृश्य के कारण पर्यटक खिंचे चले आते हैं। यहां तीन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और दो नेशनल पार्क हैं। ट्रैकिंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण के दीवानों के लिए यह जगह बेहतर है। यहां यूमियान लेक में वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है। यहां के लोगों में वॉटर स्पोर्ट्स काफी लोकप्रिय है।

चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बनी लगभग 500 गुफाएं यहां मौजूद हैं। जिनमें से कुछ ऐसी भी हैं, जो देश की सबसे लंबी और गहरी गुफा है। ये गुफाएं देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। इस राज्य का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है चेरापूंजी। यहां के अद्भुत प्राकृतिक दृश्य पूरे उत्तरी-पूर्व भारत में सबसे अनोखे और दर्शनीय हैं।

यहां कई वाटरफॉल हैं। जैसे शेदेथम फॉल्स, विनिया फॉल्स, एलिफेंट फाल्स, नोहकालीलाई, स्वीट फॉल्स, विशप्स फाल्स और लैंगशियांग फॉल्स। इन झरनों की खूबसूरती देखते बनती है। मेघालय को खैसिस, जैंटिया और गैरो हिल्स के अनुसार विभिन्न भागों में बांटा गया है। यहां कई नदियां हैं, जिनमें कुछ मौसमी हैं। इनमें से कुछ नदियां खूबसूरत वाटरफॉल बनाती हैं।

मेघालय घूमने का सबसे अच्छा मौसम है गर्मियां। वैसे आप मेघालय कभी भी जाएं गर्म कपड़ों की जरूरत हमेशा पड़ती है। सड़क, रेल और हवाई यातायात के साथ यहां हेलिकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो शिलांग से गुवाहाटी को जोड़ती है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार–समाचार

महिला ने एक साथ दिया 10 बच्चों को जन्म, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

शुरुआत में डॉक्टर्स ने स्कैन के बाद बताया था कि वह 6 बच्चे एक्सपेक्ट कर रही हैं

प्रिटोरिया(एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका में एक महिला ने एक ही प्रेग्नेंसी में 10 बच्चों को जन्म देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सात लड़को और तीन लड़कियों को जन्म दिया है। इसके लिए सी-सेक्शन ऑपरेशन कराना पड़ा। 37 वर्षीय गोसियामे थमारा सिथोल ने 7 जून को प्रिटोरिया के एक अस्पताल में 10 बच्चों को जन्म देने का दावा किया है। वह पहले से ही जुड़वा बच्चों की मां है। हालांकि इससे वह खुद भी हैरान रह गईं, क्योंकि शुरुआत में डॉक्टर्स ने स्कैन के बाद बताया था कि वह 6 बच्चे एक्सपेक्ट कर रही हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, गोसियामे थमारा सिथोल ने दावा किया कि उन्होंने प्राकृतिक तरीके से ही गर्भधारण किया था, लेकिन यह प्रेग्नेंसी उनके लिए आसान नहीं थी क्योंकि इस दौरान उन्हें पैर में बहुत दर्द और हार्टबर्न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। गोसियामे थमारा सिथोल के दावे की पुष्टि अभी तक डॉक्टरों या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा नहीं की गई है। हालांकि अगर यह दावा सही निकलता है तो यह एक ही प्रेग्नेंसी में सबसे ज्यादा बच्चों के जन्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। एक ही प्रेगनेंसी से सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड फिलहाल माली की हलीमा सिस्से के नाम है, जिन्होंने मई महीने में मोरक्को के एक अस्पताल में नौ बच्चों को जन्म दिया था। हाई-रिस्क प्रेगनेंसी को देखते हुए गोसियामे थमारा सिथोल ने यह चिंता जताई थी कि उनके बच्चे शायद जीवित न रह पाएं। हालांकि, सभी जीवित पैदा हुए हैं और अगले कुछ महीने इन्क्यूबेटरों में रखे जाएंगे। बच्चों के जन्म के बाद सिथोल के पति तेबोहो त्सोतेत्सी ने कहा कि वह खुश और भावुक दोनों हैं।

बिजली की मांग कर रहे लोगों पर गोलीबारी, तीन की मौत

गवर्नर के सुरक्षाकर्मियों ने गोली चलाई

काबुल (एजेंसी)। उत्तरी अफगानिस्तान में स्वच्छ पानी और बिजली की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोली चला दी। गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 42 अन्य जख्मी हो गए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, कई घायलों की हालत नाजुक है, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रांतीय अधिकारियों ने मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। वहीं, पुलिस का दावा है कि उनकी ओर से गोली नहीं चली है।

रिपोर्ट के अनुसार, फैजाबाद शहर में बदख्शान प्रांत के गवर्नर के दफ्तर के बाहर साफ पानी के वास्ते प्रदर्शन के लिए करीब 200 लोग जमा हुए थे। ये लोग एक नए बिजली संयंत्र के उद्घाटन के फौरन बाद पहुंचे। प्रदर्शनकारी सीबगतुल्लाह अंदेशमंद ने कहा कि हम चाहते थे कि गवर्नर मोहम्मद जकारिया सौदा उनकी मांगों पर प्रतिक्रिया दें, लेकिन उनके दफ्तर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनपर गोलीबारी कर दी।

प्रांतीय अस्पताल के चिकित्सा निदेशक शफीकुल्लाह हमदर्द ने कहा कि तीन लोगों की मौत हुई है और 42 अन्य जख्मी हुए हैं। गवर्नर के दफ्तर ने टिप्पणी के लिए संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि गवर्नर के सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है न कि पुलिस ने। उधर तालिबान ने भी फैजाबाद में हुई फायरिंग पर नाराजगी का इजहार किया है। माना जा रहा है कि अगर तालिबान इस गोलीबारी के खिलाफ हमला करता है,तब इससे इलाके में कानून व्यवस्था और बदतर हो जाएगी। अफगानिस्तान से अमेरिकी और ब्रिटिश फौज की वापसी के ऐलान के बाद से ही तालिबान ज्यादा सक्रिय हो गया है। वह लोगों के मन में अपने लिए फिर से हमदर्दी पैदा कर सत्ता पर काबिज होने की तैयारी भी कर रहा है।

12 साल से कम उम्र के बच्चों पर फाइजर की वैक्सीन का ट्रायल शुरु

न्यूयॉर्क (एजेंसी)। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने अपने टीके का ट्रायल 12 साल के कम उम्र के बच्चों पर भी शुरू कर दिया है। पहले चरण की स्टडी में कम संख्या में छोटे बच्चों को वैक्सीन की अलग-अलग खुराक दी जाएगी। इसके लिए फाइजर ने दुनिया के चार देशों में 4500 से अधिक बच्चों का चयन किया है। जिन देशों में बच्चों पर फाइजर की वैक्सीन का ट्रायल होगा है, उनमें अमेरिका, फिनलैंड, पोलैंड और स्पेन शामिल हैं। फाइजर की कोविड वैक्सीन को पहले ही अमेरिका और यूरोपीय संघ में 12 साल के अधिक उम्र की बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। हालांकि, मंजूरी आपातकालीन उपयोग के लिए ही है। फाइजर ने कोरोना की वैक्सीन अपने जर्मन पार्टनर बायोएनटेक के साथ मिलकर तैयार थी।

दुनिया के अमीर लोग नहीं भर रहे टैक्स, बेजोस, एलन मस्क का नाम चैरिटी के नाम पर बचा रहे अपना टैक्स

लंदन (एजेंसी)। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बराबर टैक्स भरते हैं। जेफ बेजोस, एलन मस्क और वॉरेन बफेट की आयकर संबंधित जानकारी लीक हुई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने 2007 और 2011 में टैक्स ही नहीं दिया। वहीं टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने 2018 टैक्स के तौर पर एक भी पैसा नहीं भरा। रिपोर्ट में अमेरिकी अरबपतियों की टैक्स संबंधी जानकारी साझा करते हुए दावा किया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे कम आयकर भर रहे हैं रिपोर्ट में कहा है कि वह अरबपतियों के आयकर पर आंतरिक राजस्व को लेकर विश्लेषण कर रही थी। वेबसाइट ने कहा कि वह आगामी हफ्तों में इससे संबंधित और विवरण जारी करेगी।

अमेरिका के सबसे अमीर 25 लोग समायोजित सकल आय का औसतन 15.8 फीसदी कर भर रहे हैं। कहा कि भले ही पिछले कुछ वर्षों में इनकी संपत्ति बढ़ी है, लेकिन ये लोग कानून रणनीति बनाकर आयकर राशि कम करते जा रहे हैं। अरबपति अपनी आयकर राशि कम करने के लिए दान व अन्य मदद के कामों में लगाई गई धनराशि का बिल दिखाकर पैसा बचा रहे हैं रिपोर्ट में फोर्ब्स पत्रिका के आंकड़ों का उपयोग कर कहा गया कि 25 सबसे अमीर अमेरिकियों की संपत्ति में 2014 से 2018 तक सामूहिक रूप से 401 अरब डॉलर की वृद्धि हुई लेकिन इस दौरान इन लोगों ने 13.6 अरब आयकर राशि का ही भुगतान किया।

बार्कशेयर हेथ्वे के सीईओ वॉरेन बफे ने 2014-2018 के दौरान सिर्फ 2.37 करोड़ डॉलर ही टैक्स रूप में भरा, जबकि इस दौरान उनकी दौलत 24.3 बिलियन डॉलर बढ़ी थी।एक इंटरव्यू में बफेट ने कहा कि उनकी मौत के बाद उनकी 99.5 फीसदी वेल्थ टैक्स और चैरिटी में चली जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा अब भी मानना है कि टैक्स सिस्टम में भारी बदलाव किया जाना

चीन के हाथियों के झुंड ने बटोरी सुर्खियां, 1 लाख डालर की फसलों का नुकसान करते हुए किया 500 किमी का सफर

बीजिंग (एजेंसी)। चीन के दक्षिण-पश्चिम इलाकों में हाथियों का एक झुंड अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। करीब 15 हाथियों का यह समूह अपनी 500 किमी की यात्रा के कारण चर्चा में है। अब इस झुंड की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें सभी सदस्य एक जगह आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। इस झुंड ने घरों, खेतों और फसलों से गुजरते हुए यह सफर तय किया है।

हाथियों ने एक लाख डॉलर की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। यह झुंड यूनान प्रांत से प्रांत की राजधानी कुनमिंग तक पहुंचा है। चीन में लगातार ड्रोन्स और कैमरे की मदद से इस झुंड की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि, इस दौरान किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है।

इस दल में सबसे पहले 16 हाथी शामिल थे, लेकिन सरकार का कहना है कि इनमें से दो वापस लौट गए और सफर के दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, झुंड में अब छह मादा और तीन पुरुष वयस्क, तीन किशोर और तीन बछड़े शामिल हैं। फिलहाल, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि हाथियों ने आखिर इतना लंबा सफर क्यों किया।

कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि झुंड का नेतृत्व करने वाला रास्ता भटक गया होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के एशियन स्पिसीज कंजर्वेशन के मैनेजर नीलंग जयसिंह के अनुसार एशियन हाथी अपने घरों को लेकर काफी वफादार होते हैं।

लेकिन बदलाव होने, संसाधनों की कमी या विकास होने की स्थिति में वे अपनी जगह बदल सकते हैं। सरकार ने लोगों को घर के अंदर रहने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही घर के बाहर मक्का या नमक नहीं रखने के लिए कहा है। साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि पटाखों का इस्तेमाल न करें, इससे हाथी डर सकते हैं।

तुर्की में एक गोताखोर समुद्र के अंदर के हालातों को देखते हुए। तुर्की सरकार ने समुद्री स्नोट को हटाने का अभियान शुरु किया है।

टेक्सास में उर्जा से जुड़े विधेयक पेश करते हुए रिपब्लिकन क्रिस पेडी सिनेटर कैली हेनकॉक व टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबोट।

जूनो अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा गैनीमेड के बर्फीले कक्षा की तस्वीर भेजी

वॉशिंगटन (एजेंसी)। नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा के सबसे करीब उड़ान भरने के बाद बर्फीले कक्षा की झलक पेश करते हुए दो चित्र भेजे हैं। 7 जून को उड़ान के दौरान, जूनो बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड की सतह के 645 मील (1,038 किलोमीटर) के भीतर आया और जुपिटर ऑर्बिटर के जूनोकैम इमेजर और इसके स्टेलर रेफरेंस यूनिट स्टार कैमरा से दो चित्र लिए। तस्वीरें गैनीमेड की सतह को विस्तार से दिखाती हैं, जिसमें क्रेटर, स्पष्ट रूप से अलग डार्क और ब्राइट टेरेन और लंबी संरचनात्मक विशेषताएं संभवतः टेक्टोनिक दोषों से जुड़ी हुई हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट के जूनो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर स्कॉट बोल्टन ने कहा, यह इस पीढ़ी में इस विशाल चंद्रमा के लिए सबसे निकटतम अंतरिक्ष यान है।'

बोल्टन ने कहा, 'हम किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष को निकालने से पहले अपना समय लेने जा रहे हैं, लेकिन तब तक हम इस खगोलीय घटना पर आश्चर्य कर सकते हैं। अपने हरे रंग के फिल्टर का उपयोग करते हुए, अंतरिक्ष यान के जूनोकैम दृश्य-प्रकाश इमेजर ने पानी-बर्फ से घिरे चंद्रमा के लगभग पूरे हिस्से को कैप्चर कर लिया। बाद में, जब कैमरे के लाल और नीले रंग के फिल्टर को शामिल करते हुए उसी छवि के संस्करण नीचे आते हैं, तब इमेजिंग विशेषज्ञ गैनीमेड का एक रंगीन चित्र प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, जूनो की स्टेलर रेफ्रेंस यूनिट गैनीमेड के अंधेरे पक्ष (सूर्य के विपरीत पक्ष) की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर प्रदान की, जो बृहस्पति से बिखरे हुए मंद प्रकाश में नहाया हुआ था। आने वाले दिनों में अंतरिक्ष यान अपने गैनीमेड फ्लाईबाई से और तस्वीरें भेजेगा। गैनीमेड बुध ग्रह से बड़ा है और सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा है, जिसका अपना मैग्नेटोस्फीयर है।

माउंटरोस काउंटी इलाके के जंगलों में लगी आग के बाद उठता हुआ

हंगरी में चीन को चिढ़ने रोड का नाम, फ्री हांगकांग रोड, दलाई लामा रोड

बुडापेस्ट (एजेंसी)। हंगरी में बन रहे चीनी यूनिवर्सिटी के कैंपस के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को हजारों लोगों की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए संसद भवन का घेराव किया है। लोगों के गुस्से को देखकर राजधानी बुडापेस्ट के मेयर ने प्रस्तावित फुडान यूनिवर्सिटी कैंपस के पास की सड़कों का नाम ही बदल दिया है। चीन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर सड़कों के नाम फ्री हांगकांग रोड, दलाई लामा रोड, उइगुर शहीद रोड और बिशप झी शिगुआंग रोड रखा गया है। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर बाकायदा बोर्ड लगाकर चीन को भड़काने वाले नाम लिखे गए हैं।

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि चीन अपनी यूनिवर्सिटी के जरिए उनके देश में कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने काम करेगा। इतना ही नहीं, कैंपस के बनने से हंगरी की उच्च शिक्षा के स्तर में कमी आएगी। हंगरी की सरकार और चीन के बीच काफी मजबूत संबंध है। राष्ट्रवादी पार्टी होने के बावजूद निवेश के लिए हंगरी सरकार कम्युनिस्ट विचारधारा वाले चीन को नाराज नहीं करना चाहती। लोगों के विरोध के कारण इस यूनिवर्सिटी के निर्माण का काम प्रभावित हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस को करीब 1.8 अरब डॉलर की लागत से बनाया जा रहा है। यह राशि पिछले साल हंगरी में शिक्षा पर खर्च हुए कुल बजट से कई गुना ज्यादा है। लेकिन, लोगों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के कारण हंगरी की सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

लोगों का दावा है कि चीन विश्वविद्यालय के जरिए यूरोप में कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाना चाहता है। विश्वविद्यालय का बुडापेस्ट परिसर 2024 तक बनकर तैयार होने की बात है। योजना को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का समर्थन प्राप्त है।

कोलंबिया में फीफा विश्व कप क्वालीफायर मुकाबले का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

छेड़खानी के चौथे दिन उधना पुलिस ने विशाल गुरु भूषण पाटिल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया

क्रांति समय दैनिक

सूरत के उधना क्षेत्र में गांधी कुटीर सोसायटी में रहने वाले एक युवक ने १५ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है. किशोरी के साथ विशाल उर्फ भूषण पाटिल ने दुष्कर्म किया। छत पर अकेलेपन का फायदा उठाकर किशोरी से शारीरिक छेड़छाड़ किया था. छेड़छाड़ के चौथे दिन पुलिस ने पॉक्सो समेत मामला दर्ज कर लिया है। छेड़छाड़ के आरोपी के सामने विशाल के भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं के साथ होने की तस्वीरें सामने आई हैं।

विशाल पाटिल ने किशोरी के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने के बाद भयभीत हुई , उसके बाद में किशोरी ने घटनाक्रम के बारे में अपने परिजनों से बात की ।जब पता चला कि युवक ने अपनी

बेटी के साथ इस तरह की घटना की है तो परिजनों ने उधना पुलिस से संपर्क किया। जहां पीड़ित किशोरी ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. आरोपी विशाल उर्फ भूषण पाटिल, से पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद छत पर अकेलापन का फायदा उठाया और किशोरी के साथ शारीरिक छेड़छाड़ किया।

विशाल उर्फ भूषण के खिलाफ उधना थाने में पॉक्सो वन के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि पीड़िता नाबालिग है. विशाल भूषण पाटिल गांधी कुटीर सोसायटी में रहते हैं।

सूत्रों के मुताबिक विशाल पाटिल बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं. भूषण पाटिल का यह कृत्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

एकाउंट डिलीट किए जाने पर आम आदमी पार्टी (आप) की नगर पार्षद पायल पटेल

‘आप’ की महिला नगर पार्षद का ट्वीटर एकाउंट डिलीट, खाडी सफाई को लेकर उठाए थे सवाल

क्रांति समय दैनिक

सूरत,शहर की महिला नगर पार्षद पायल पटेल का ट्वीटर एंकाउंट डिलीट कर दिया गया है। एकाउंट डिलीट किए जाने पर आम आदमी पार्टी (आप) की नगर पार्षद पायल पटेल का आरोप है कि उन्होंने खाडी सफाई को लेकर सत्ता पर सवाल उठाए थे। जिससे बौखलाई भाजपा के आईटी

सेल द्वारा ट्वीटर को रिपोर्ट कर मेरा एकाउंट डिलीट करवा दिया। पायल पटेल ने कहा कि वह खामोश नहीं रहेंगी और अन्य माध्यमों के जरिए आवाज बुलंद करती रहूंगी। पायल पटेल ने बताया कि उनका ट्वीटर एकाउंट डिलीट कर दिया गया। किस कारण ट्वीटर एकाउंट डिलीट किया गया है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि खाडी सफाई मुद्दे को लेकर मैंने सत्तापक्ष के खिलाफ कई ट्वीट किए थे। जिससे बौखलाई भाजपा के आईटी सेल द्वारा ट्वीटर को रिपोर्ट करने से एकाउंट डिलीट किया हो सकता है। पायल पटेल ने कहा कि इसके बावजूद वह सच्चाई सामने लाती रहेंगी। ट्वीटर नहीं तो सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से मेरी सच की लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि 22 वर्षीय पायल किशोरभाई साकरिया सूरत के वार्ड नंबर 16 से आप की नगर पार्षद हैं। सूरत के पुणा क्षेत्र निवासी पायल पटेल ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और सबसे कम उम्र की पार्षद हैं।

‘मां-अमृतम वात्सल्य’ योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्तिकार्ड जारी होगा : नितिन पटेल

क्रांति समय दैनिक

उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि नागरिकों को आकस्मिक परिस्थितियों और गंभीर बीमारियों के दौरान त्वरित उपचार मुहैया कराने के लिए राज्य में ‘मां-अमृतम वात्सल्य’ योजना कार्यरत है ।योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति परिवार एक कार्ड दिया जाता था। लेकिन अब प्रत्येक लाभार्थी को व्यक्तिगत कार्ड देने का स्वास्थ्य विभाग ने फैसला किया है। नितिन पटेल ने बताया कि मां, मां वात्सल्य कार्ड के नागरिकों को अब सरकारी अस्पतालों से कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा आयुष्यमान भारत, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना, मां योजना और मां मात्सल्य योजना के अंतर्गत निर्धारित मापदंड के दायरे में आनेवाले प्रति परिवार वार्षिक रु 5 लाख तक स्वास्थ्य कवच निश्शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मां या मां वात्सल्य कार्ड धारक लाभार्थी योजना के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी सरकारी/ ट्रस्ट संचालित या निजी अस्पतालों में उपचार करवा सकेंगे। भारत सरकार के प्रावधानों के मुताबिक राज्य में मां अमृतम और मां अमृतम वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को पहले प्रति परिवार एक कार्ड दिया जाता था। उसके बदले अब प्रत्येक लाभार्थी को व्यक्तिगत कार्ड जारी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल राज्य के सरकारी अस्पताल, सामूहिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नए कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरूकर दी गई है। जहां सभी लाभार्थी अपना नया कार्ड निकलवा सकते हैं।

सार-समाचार

गुजरात में मॉन्सून की दस्तक, वलसाड में धमाकेदार एन्ट्री

अहमदाबाद,मॉन्सून ने गुजरात में दस्तक दे दी है और इसकी शुरुआत दक्षिण गुजरात के वलसाड से की है। मौसम विभाग ने इसकी अधिकृत घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में मॉन्सून का आगमन हो गया है। हांलाकि दक्षिण गुजरात को छोड़ राज्य के अन्य हिस्सों में मॉन्सून की फिलहाल प्रतीक्षा करनी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी पांच दिन दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी, तापी, सूरत और डांग जिलों में बारिश होगी, जिसे देखते हुए अगले तीन से पांच दिन मछुआरें समुद्र में न जाएं। गौरतलब है मुंबई में धुआंधार बैटिंग करने के बाद मॉन्सून ने दक्षिण गुजरात का रुख किया है। जिसकी वजह से दक्षिण गुजरात के जिलों में बरसाती माहौल है। आमतौर पर केरल में मॉन्सून की आगमन के 15 दिनों के बाद गुजरात में मॉन्सून दस्तक देता है। लेकिन इस वर्ष छह दिन पहले ही गुजरात में मॉन्सून ने दस्तक दी है। मुंबई में भी समय से पहले मॉन्सून का आगमन हुआ है। मंगलवार के बाद आज बुधवार को वलसाड में बारिश हुई है। देर रात से वलसाड जिले के कपराडा में उल्लेखनीय बारिश हुई है। कपराडा के साथ ही वलसाड के वापी समेत अन्य इलाकों में बारिश होने की खबर है। वलसाड से सटे केन्द्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में भारी बारिश हुई।

कोर्ट बंद रहने से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं वकील, 476 वकीलों ने सनद जमा करवाई

अहमदाबाद,कोरोना महामारी का व्यापार-व्यवसाय पर बुरा असर हुआ है। इससे वकालत का व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं है। गत 14 महीनों में कोर्ट कार्यवाही ठप्प होने के कारण राज्य के 98,441 वकीलों की आय पर विपरीत असर से उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे 476 वकीलों ने वकालत छोड़कर अन्य नौकरी और व्यवसाय शुरू कर बार काउन्सिल में अपनी सनद जमा करवा दी है। बार काउन्सिल के वरिष्ठ सदस्य अनिल केला के मुताबिक गत 14 महीनों से न्यायालय बंद थे। न्यायालयों में वकालत करनेवाले 90 से 95 प्रतिशत वकीलों की आय पर विपरीत असर पड़ा है। जिससे वे अन्य व्यवसाय में जाने के लिए मजबूर हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए वरिष्ठ वकील प्रकाश पटेल ने भी बताया कि तहसील और जिला स्तर पर कोर्ट की बिल्डिंगों का निर्माण आधुनिक तौर पर किया गया है।

क्रांति समय
Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

कृषि कानूनों को खत्म करना ही किसान आंदोलन का एकमात्र समाधानः कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना ही किसान आंदोलन के मुद्दे का एकमात्र समाधान है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान 500 किसानों की मौत होने के दावे वाले हैशटैग के साथ ट्वीट किया, ''खेत-देश की रक्षा में तिल-तिल मरे हैं किसान, पर ना डरे हैं किसान, आज भी खरे हैं किसान।'' कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, '' किसान को भीख नहीं, न्याय चाहिए। किसान को अहंकार नही, अधिकार चाहिए। घमंड के सिंहासन से उतरिए, राजहठ छोड़िए, तीनों काले क़ानून ख़त्म करना ही एकमात्र रास्ता है'' गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से कई किसान संगठन दिल्ली के निकट कुछ स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की है।

किसान नेता ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, आंदोलन के लिए मांगेंगे समर्थन

कोलकाता। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में किसान नेता कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के वास्ते बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। बीकेयू के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा, ''हम चुनावी जीत के लिए ममता बनर्जी को धन्यवाद देने के साथ किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित एमएसपी दिलाने के कदम के लिए उनका समर्थन चाहते हैं।'' सिंह ने कहा कि वह बनर्जी से पश्चिम बंगाल में फलों, सब्जियों और दुग्ध उत्पादों के लिए एमएसपी तय करने की मांग करना चाहते है क्योंकि यह बाकी जगहों पर ''एक मॉडल की तरह काम करेगा।'' टिकैत और अन्य किसान नेता पिछले एक साल से संसद द्वारा पारित तीन कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन कानूनों से खेतीबाड़ी का बाजारीकरण हो जाएगा और छोटे किसानों को बड़ी खुदरा कंपनियों के शोषण से पर्याप्त सुरक्षा भी नहीं मिलेगी।

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएः मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने कोविड-19 से बचाव के लिए मुफ्त टीकाकरण के फैसले को 'देर आयद दुरुस्त आयद' ठहराते हुए बुधवार को कहा कि अब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मायावती ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट में कहा देश में कोरोना महामारी के प्रकोप की दूसरी लहर के अति-घातक सिद्ध होने के बाद अब आगे इससे बचाव के लिए 21 जून से सभी के लिए मुफ्त टीकारकण का केन्द्र का फैसला देर से सही लेकिन उचित कदम है। हालाँकि बसपा इसकी माँग शुरू से ही करती रही है।

झारखंड के दुमका में आकाशीय बिजली गिरी, घटना में 5 लोगों की मौत

दुमका/रामगढ़/लातेहार। झारखंड के दुमका तथा रामगढ़ जिलों में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने की विभिन्न घटनाओं में एक बालक समेत पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि कई अन्य घायल हो गये। वहीं लातेहार में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों कीमृत्यु हो गयी। दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने की एक घटना जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के तहत आने वाले कुंजबोना गांव में हुई, जिसमें शिवशंकर मुर्मू नामक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गयी, वहीं उसके दो मित्र बेहोश हो गये।

किसानों के लिए लाभकारी एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाए केंद्रः किसान मोर्चा

नयी दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को केंद्र सरकार से सभी किसानों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून तत्काल लागू करने की मांग की। मोर्चा ने एक बयान में कहा कि ईंधन एवं अन्य चीजों की कीमत में इजाफा होने के कारण किसान अपनी फसल की लागत तक नहीं निकाल पा रहा है। उन्होंने कहा, पंजाब में मक्का किसानों को 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है जबकि इसका एमएसपी 1850 रुपये प्रति क्विंटल है। संयुक्त किसान मोर्चा सभी फसलों के लिए लाभकारी एमएसपी की गारंटी वाला कानून तत्काल लागू करने की मांग करता है। वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले पंजाबी गायक जैजीबी का ट्विटर एकाउंट बंद किए जाने की भी आलोचना की। साथ ही सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने और इसका समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्वाई किए जाने का भी आरोप लगाया।

कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर तैयारी करेंः नितिन गडकरी

प्रयागराज। (एजेंसी)।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है और राज्यों को ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। प्रयागराज के नैनी स्थित सरस्वती हाईटेक सिटी में प्रभाव्य इंडस्ट्रीज के आक्सीजन संयंत्र के शिलान्यास कार्यक्रम को दिल्ली से ऑनलाइन संबोधित करते हुए गडकरी ने कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह से अनुरोध किया कि वे प्रदेश के हर जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों में हवा से ऑक्सीजन बनाने का संयंत्र लगाना अनिवार्य करें।

मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में तीसरी लहर और चौथी लहर का संकट है और इसको ध्यान में रखकर काम करना आवश्यक है। इसके साथ ही हर जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की स्थिति देखना जरूरी है। आवश्यकता पड़े तो राज्य सरकार द्वारा हर जिले की चिकित्सा व्यवस्था में 4,000-5,000 सिलेंडर शामिल किया जाए। गडकरी ने प्रभाव्य इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक उमेश जायसवाल की पहल की सराहना करते हुए कहा, ÷मैं उद्योग, व्यापार और निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य उद्योगपतियों से भी समाज के प्रति संवेदनशीलता दिखाकर इस तरह के कार्य करने का अनुरोध करता हूं।÷ मंत्री ने कहा, ÷रेड फंगस और ब्लैक फंगस के लिए भी हमने इंजेक्शन बनाया है और आज ही पुणे में 10,000 इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ये इंजेक्शन हम सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश को भी दे सकते हैं। इसे हमने 1250 रुपये में बनाया है।÷ उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनी 4.50 लाख रुपये से 6.50 लाख रुपये में वेंटिलेटर उपलब्ध कराती है। वहीं विशाखापत्तन के एमएसएमई में 1.48 लाख रुपये में तैयार 500 वेंटिलेटर निःशुल्क वितरित किए गए हैं। मांग आने पर उत्तर प्रदेश को ये वेंटिलेटर 1.48 लाख रुपये में उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई तरह के संकट में प्रदेश सरकार ने काफी प्रयास किए। भविष्य में इस प्रकार का कोई संकट ना आये, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश में विभिन्न आकार के 416 नए ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे आने वाले चार पांच महीने में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। प्रभाव्य इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक उमेश जायसवाल ने बताया कि 15.76 करोड़ रुपये की लागत से लगने वाला नया ऑक्सीजन संयंत्र अगले तीन महीने में स्थापित हो जाएगा। इस संयंत्र से 350 घन मीटर प्रति घंटे ऑक्सीजन उत्पादन का लक्ष्य है।

अखिलेश का आरोप, भाजपा सरकार को किसानों की रत्ती भर भी फिक्र नहीं

लखनऊ। (एजेंसी)।

समाजवादी पार्टी (सपा)अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि भाजपा सरकार को किसानों की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा,'' भाजपा के चार साल किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं। तीन काले कृषि कानून लाकर किसानों को बड़े पूंजीघरानों का आश्रित बना दिया गया है, न किसान को फसल का दाम मिल रहा है और न हीं उससे किए गये वादे पूरे हो रहे हैं। पिछले दिनों हुई बरसात में हजारों टन गेहूं क्रय केंद्रों में खुले में पड़े रहने से बर्बाद हो गए। किसानों को बहाने बनाकर परेशान किया जा रहा है।''

उन्होंने आरोप लगाया, ''प्रदेश में भाजपा सरकार को किसानों की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। उनकी धान की फसल भी वैसे ही बर्बाद हुई, जैसा आज गेहूं की फसल के साथ हो रहा है। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला है। भाजपा सरकार ने किसानों के साथ कोई वादा नहीं निभाया। उल्टे उसे खेत के मालिक की जगह मजदूर बनाने का कुचक्र रच दिया।'' उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने फतेहपुर, संभल, अमरोहा, चित्रकूट, कन्नौज तथा फर्रुखाबाद में गेहूं खरीद केंद्रों पर तौल बंद किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा,'' इसकी वजह से किसानों को जबरदस्त मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों क्विंटल गेहूं तौल के इंतजार में पड़ा है। किसान टोकन लेकर भटक रहे हैं। मंडी में गेहूं खुले में पड़ा है, बारिश के अंदेशे के बावजूद बचाव का कोई प्रबंध नहीं है।'' उन्होंने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीति भाजपा को भारी पड़ेगी। किसान 2022 के चुनाव के इंतजार में हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर किसानों के साथ न्याय हो सकेगा।

सचिन पायलट फिर नाराज, राजस्थान की राजनीति में फिर तेज हुई सरगर्मी

जयपुर। (एजेंसी)।

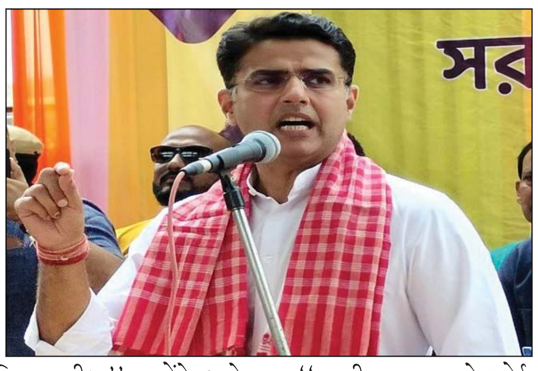

कांग्रेस नेता सचिन पायलट द्वारा उठाये गए मुद्दों पर आलाकमान की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने संबंधी बयान के बीच राजस्थान में एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड ने मंगलवार को कांग्रेस में कथित तौर पर बढ़ते असंतोष का हवाला देते हुए ट्वीट किया तो पूर्व उपमुख्यमंत्री पायलट ने उन्हें अपनी पार्टी यानी भाजपा की आंतरिक कलह को देखने की सलाह दी। पायलट के साक्षात्कार के बाद राठौड़ ने ट्वीट किया ''आखिर मन का दर्द होठों पर आ ही गया। ये चिंगारी कब बारूद बनकर फूटेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने अहम भूमिका निभाई थी। सुलह कमेटी के पास मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। ना जाने कब क्या हो जाए...''।

पायलट ने इसकी प्रतिक्रिया में ट्वीट किया, '' राज्य के भाजपा नेताओं को व्यर्थ बयानबाजी के बजाय अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपसी फूट व अंतर्कलह इतनी हावी है कि राज्य में भाजपा विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। '' उन्होंने आगे कहा,''इनकी नाकाम नीतियों से देश में उपजे संकट में जनता को अकेला छोड़ने वालों को जनता करारा जवाब देगी।''हालांकि, पायलट से इस मुद्दे पर बात करने के लिए जब सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनके द्वारा उठाये गये मुद्दो पर 10 महीने पूर्व गठित केन्द्रीय समिति द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल फेरबदल का इंतजार पायलट खेमे के लोग कर रहे है। इससे पूर्व पायलट समर्थक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी जिन्होंने हाल ही में कुछ मुद्दों को लेकर सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भेजा दिया था।

पायलट खेमे के अन्य नेताओं में शामिल वेद प्रकाश सोलंकी, रमेश मीणा ने हाल ही में सरकार के विरोध अपनी आवाज उठाते हुए चिंताएं व्यक्त की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेन्द्र ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि पार्टी आलाकमान ने कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। सिंह से संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी आलाकमान अथवा प्रभारी महासचिव से जो भी बातचीत हुई है.. उन्हें इसे पूरा करना चाहिए। यदि उन्होंने कोई मुद्दा उठाया तो मैं नहीं समझता उसमें कुछ गलत है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जुलाई में मुख्यमंत्री गहलोत के प्रति नाराजगी दिखाते हुए अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा चले गए थे। उस समय पायलट को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद वे वापस लौट आये। आलाकमान ने उनके द्वारा उठाये गये मुद्दो के समाधान के लिये एक समिति का गठन किया था।

हमने राजनीतिक संबंधों की परवाह किये बगैर व्यक्तिगत संबंधों को महत्व दिया हैः शिवसेना

मुंबई। (एजेंसी)।

शिवसेना ने बुधवार को कहा कि उसने राजनीतिक संबंधों की परवाह किये बगैर हमेशा व्यक्तिगत संबंधों को महत्व दिया है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार की मुलाकात व्यक्तिगत संबंधों के साथ-साथ प्रोटोकॉल का भी हिस्सा थी। प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक के बाद, ठाकरे ने मंगलवार को कहा था कि इस तरह की बातचीत करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था कि वह पाकिस्तानी नेता नवाज शरीफ से मिलने नहीं गए थे।

शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में कहा गया है, ''मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा राजनीतिक कारणों से नहीं था। जो लोग इसमें राजनीति देखते हैं..... उन्हें अपनी सोच से खुश होने दें। इस बैठक को लेकर बहुत सारी अटकलें होंगी। हम केवल यह उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के साथ लंबित मुद्दे केंद्र जल्द हल करे।'' ठाकरे ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था जिसमें उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता अजित पवार, और कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मोदी से मुलाकात की थी और राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। यह बैठक डेढ़ घंटे चली थी और ठाकरे ने प्रधानमंत्री के साथ अकेले में भी बैठक की थी। संपादकीय में महाराष्ट्र में भाजपा नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है कि उन्हें बैठक के संदर्भ में मोदी-ठाकरे संबंधों की प्रकृति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कहा गया है, ''हमें इस बात में संदेह नहीं है कि माहौल अच्छा था और बैठक एक दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई थी।'' किसी भी राज्य का नाम लिए बिना शिवसेना ने कहा कि मोदी और ठाकरे के बीच बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि केंद्र और महाराष्ट्र के बीच कोई गतिरोध नहीं है। संपादकीय में कहा गया है, ''महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री का दृढ़ मत है कि राज्य को उसका सही हिस्सा मिलना चाहिए।

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक टली

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

डोमिनिका उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद चोकसी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। चोकसी के स्थानीय वकीलों के दल ने यह याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत के न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई शुरू की। 'डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन' की खबर के मुताबिक सरकारी पक्ष के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि चोकसी देश छोड़कर भाग सकता है। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी। उच्च न्यायालय चोकसी के विधिक दल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भी सुनवाई कर रहा था और उसकी सुनवाई भी स्थगित कर दी गई।

जितिन के कांग्रेस छोड़ने पर बोले खड़गे- जाने वाले जाते रहते हैं, सिंधिया ने छोटे भाई का किया स्वागत

नई दिल्ली (एजेंसी)।

कांग्रेस के युवा और वरिष्ठ नेता रहे जितिन प्रसाद ने पार्टी का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जितिन प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में भाजपा कार्यालय में भगवा पार्टी की सदस्यता हासिल की। जितिन प्रसाद के इस कदम को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जाने वाले जाते रहते हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते। यह उनका निर्णय है। उनका कांग्रेस में भविष्य था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

वहीं, पिछले साल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जितिन प्रसाद का स्वागत किया और उन्हें अपना छोटा भाई बताया। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका करार देते हुए कहा कि उनकी पार्टी को राज्यों में जीत हासिल करने के लिए जन नेताओं की पहचान कर उन्हें मजबूती प्रदान करनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिश्नोई ने ट्वीट किया, ''पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ... और अब जितिन प्रसाद ...। कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि हम उन नेताओं को खो रहे हैं जिन्होंने पार्टी को दिया और आगे भी दे सकते थे।''

बिश्नोई ने यह भी कहा, ''इससे मैं सहमत हूं कि उन्हें कांग्रेस को, खासकर इस मुश्किल समय में नहीं छोड़ना चाहिए था। परंतु कांग्रेस को जन नेताओं की पहचान करके उन्हें मजबूत करना चाहिए ताकि राज्यों में फिर से जीत हासिल की जा सके।'' आपको बता दें कि जितिन प्रसाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जितेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं जिन्होंने पार्टी में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी थीं। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था। जितिन प्रसाद ने 2004 में शाहजहांपुर से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था और उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में इस्पात राज्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने 2009 में धौरहरा सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने संप्रग सरकार में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन और राजमार्ग और मानव, संसाधन विकास राज्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले जितिन प्रसाद को 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

कोर्ट ने केन्द्र से कहा, कोरोना के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा रुख अपनाए

मुंबई। (एजेंसी)।

बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए केन्द्र सरकार का रुख सीमाओं पर खड़े होकर वायरस के आने का इंतजार करने की बजाय ''सर्जिकल स्ट्राइक'' करने जैसा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की एक पीठ ने कहा कि केन्द्र सरकार का नया ''घर के पास'' (नीयर टू होम) टीकाकरण कार्यक्रम केन्द्र तक संक्रमण वाहक के आने का इंतजार करने जैसा है। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, '' कोरोना वायरस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें उसे खत्म करने की जरूरत है। यह शत्रु कुछ निश्चित स्थानों और कुछ लोगों के भीतर है, जो बाहर नहीं आ सकते। सरकार का रुख 'सर्जिकल स्ट्राइक' करने जैसा होना चाहिए। वहीं, आप सीमाओं पर खड़े होकर संक्रमण वाहक के आपके पास आने को इंतजार कर रहे हैं। आप दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल हीं नहीं हो रहे।'' पीठ ने कहा कि सरकार व्यापक रूप से जनता के कल्याण के लिए फैसले कर रही थी,लेकिन उसने काफी देरी कर दी जिस कारण कई लोगों की जान चली गई।

अदालत वकील धृति कपाड़िया और कुणाल तिवारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में सरकार को 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, दिव्यांगों और 'व्हीलचेयर' आश्रित या बिस्तर से उठ ना सकने वाले लोगों के लिए घर-घर जाकर टीकाकरण कार्यक्रम चलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। केन्द्र सरकार ने मंगलवार को अदालत से कहा था कि वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, 'व्हीलचेयर' आश्रित या बिस्तर से उठ ना सकने वाले लोगों का घर-घर जाकर टीकाकरण संभव नहीं है। हालांकि, उसने ऐसे लोगों के लिए घर के पास टीकाकरण केन्द्र शुरू करने का निर्णय किया है। उच्च न्यायालय ने केरल, जम्मू-कश्मीर, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र के वसई-विरार जैसे कुछ नगर निगमों में घर-घर जाकर टीकाकरण करने के लिए चल रहे कार्यक्रम का बुधवार को उदाहरण दिया। अदालत ने कहा, '' देश के अन्य राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? केन्द्र सरकार घर-घर जाकर टीकाकरण करने को इच्छुक राज्यों और नगर निगमों को रोक नहीं सकती लेकिन फिर भी वे केन्द्र की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं।'' अदालत ने यह भी पूछा कि केवल बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को ही क्यों घर-घर टीकाकरण कार्यक्रम के लिए केन्द्र की अनुमति का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि उत्तर, दक्षिण और पूर्व में कई राज्य बिना अनुमति के यह कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं।

मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, '' केवल पश्चिम को ही क्यों इंतजार करना पड़ रहा है?'' पीठ ने कहा कि बीएमसी भी यह कहकर अदालत की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रही है कि वह घर-घर जाकर टीकाकरण शुरू करने को तैयार है, अगर केन्द्र सरकार इसकी अनुमति दे। अदालत ने कहा, '' हम बीएमसी की हमेशा तारीफ करते रहे हैं और कहते आए हैं कि वह अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श है।'' उसने कहा, '' मेरा बीएमसी से सवाल यह कि अभियान की शुरुआत में, कई वरिष्ठ राजनेताओं को मुंबई में उनके घर पर टीके लगाए गए। ये किसने किया? बीएमसी या राज्य सरकार? किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।'' पीठ ने बीएमसी के वकील अनिल सखारे और राज्य की ओर से पेश हुई अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि किस प्राधिकरण ने राजनेताओं को उनके आवास पर टीका लगाए। अदालत ने केन्द्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह को भी मामले पर एक बार फिर विचार करने का निर्देश दिया। पीठ ने इसमामले में अब 11 जून को आगे सुनवाई करेगी।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)